



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276194
CG-DL-E-15092026-276194

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 239]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी (एए) – 01/2026

विषय: चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए गए 'ग्लूफोसिनेट और इसके लवण' के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की अवशेषण जांच।

फा. सं. 7/02/2026- डीजीटीआर.— सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों की पहचान, मूल्यांकन और एंटी-डंपिंग शुल्क का संग्रहण और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, संशोधित के अनुसार, नामित प्राधिकारी द्वारा मुझे चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए गए 'ग्लूफोसिनेट और इसके लवण' के आयात से संबंधित एंटी-अवशेषण जांच के मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है।

जांच की पृष्ठभूमि

- एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार, सुपरफॉर्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड, एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी, यूपीएल सस्टेनेबल

एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड और एसडब्ल्यूएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें चीन पीआर (इसके बाद "विषय देश" कहा गया है) से उत्पन्न या निर्यात किए गए 'ग्लूफोसिनेट और इसके लवण' (इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण का आरोप लगाया गया।

2. चीन जनवादी गणराज्य से ग्लूफोसिनेट और इसके लवण के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच अधिसूचना सं. 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 जून 2024 द्वारा आरंभ की गई थी। अंतिम निष्कर्ष एफ. सं. 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी 2025 के माध्यम से, प्राधिकारी ने 5 वर्षों की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य से ग्लूफोसिनेट और इसके लवण के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की। ऐसे शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 09/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 8 मई 2025 के माध्यम से लगाए गए थे। नीचे दी गई तालिका वर्तमान में लागू शुल्क को दर्शाती है:

क्रम संख्या	एचएस कोड	उत्पादक	राशि
1	38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 और 38089999	कोई भी उत्पादक	2,998 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन

3. अधिनियम की धारा 9ए(1बी) और नियमों के नियम 29(2) के अनुसार, जहां एंटी-डंपिंग शुल्क के अधीन कोई लेख ऐसी कीमत पर या ऐसी शर्तों के तहत भारत में आयात किया जाता है, जिसे मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क का अवशोषण माना जाता है, जिससे वह शुल्क अप्रभावी हो जाता है या हो सकता है, वहाँ नामित प्राधिकारी, समीक्षा करने के बाद, डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद शुल्क के रूप या आधार और/या एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा में संशोधन की सिफारिश कर सकता है। इसी के अनुसार, प्राधिकारी को, घरेलू उद्योग या किसी अन्य हितधारक द्वारा या उनकी ओर से पर्याप्त साक्ष्य के साथ दायर आवेदन के आधार पर, यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क शुल्क के अवशोषण के कारण अप्रभावी हो गया है या हो सकता है।
4. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/02/2026-डीजीटीआर दिनांक 2 मार्च 2026 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसमें अधिनियम की धारा 9ए और नियमों के नियम 30 के अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात पर एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण के अस्तित्व और प्रभाव का निर्धारण करने तथा एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा या रूप में संशोधन की सिफारिश करने के लिए विषय जांच आरंभ की गई।

क . प्रक्रिया

5. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
1. आरंभ
 - i. प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/02/2026-डीजीटीआर दिनांक 2 मार्च 2026 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की, जिसमें विषय देश से विषय वस्तु के आयात के विरुद्ध अवशोषण जांच आरंभ की गई।
 - ii. नियम 30(4) के अनुसार, जांच आरंभ होने से पहले, विषय देश की सरकार को उनके भारत स्थित दूतावास के माध्यम से वर्तमान अवशोषण आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया गया था।

- iii. नियम 6(2) के अनुसार, हितधारकों को आरंभ अधिसूचना की एक प्रति विषय देश के भारत स्थित दूतावास, विषय देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में विषय वस्तु के ज्ञात आयातकों और अन्य हितधारकों को, आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, साझा करके जांच आरंभ होने की सूचना दी गई थी।
2. **जांच अवधि (पीओआई)**
 - i. जैसा कि आरंभ अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, अवशोषण अवधि जनवरी 2025 से सितंबर 2025 (9 माह) मानी गई थी। प्राधिकारी ने ऐसी अवधि में कीमतों की तुलना मूल जांच की जांच अवधि, अर्थात् 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 ("मूल पीओआई") से की है।
3. **आयात डेटा**
 - i. अवशोषण अवधि के लिए विषय वस्तु का लेन-देन-वार आयात डेटा प्राप्त करने के लिए डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। डेटा प्राप्त किया गया था और उचित परीक्षण के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए उस पर भरोसा किया गया है। आयात की मात्रा और मूल्य को डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आंकड़ों के आधार पर माना गया है।
4. **आवेदन की गैर-गोपनीय प्रति का वितरण**
 - i. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन की गैर-गोपनीय प्रति की एक प्रति विषय देश की सरकार को उनके भारत स्थित दूतावास के माध्यम से, विषय देश से विषय वस्तु के ज्ञात निर्यातकों को, भारत में ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को और अन्य हितधारकों को, जिन्होंने आवेदन की एक प्रति के लिए लिखित में अनुरोध किया था, प्रदान की गई थी।
5. **विषय देश के निर्यातकों द्वारा भागीदारी**
 - i. नियम 6(4) के अनुसार, सामान्य मूल्य और शुद्ध निर्यात मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी गई थी: लियर केमिकल कंपनी लिमिटेड; एग्रोड्रैगन कंपनी लिमिटेड; बीएएसएफ; शेडोंग बिनॉंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; लिमेन केमिकल कंपनी लिमिटेड; फुहुआ टोंगडा एग्रो-केमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; योंगनॉंग बायोसाइंसेज कंपनी लिमिटेड; जियांगसू हुइफेंग बायो एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड; शंघाई किझोउ ज़ियुई कंपनी लिमिटेड; और वेइफांग ज़िनलु केमिकल कंपनी लिमिटेड।
 - ii. निर्यातक प्रश्नावली विषय देश की सरकार को भी उनके भारत स्थित दूतावास के माध्यम से भेजी गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे इसे विषय वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को अग्रेषित करें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने की सलाह दें।
 - iii. जवाब में, विषय देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का जवाब दायर किया: (1) जियांगशुई झोंगशान बायोसाइंसेज कंपनी लिमिटेड; और (2) झेजियांग झोंगशान केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड। दोनों कंपनियाँ संबद्ध हैं, पूर्व उत्पादक है और बाद वाली निर्यातक है, और उन्हें एक साथ "भाग लेने वाले निर्यातक" के रूप में संदर्भित किया गया है।

6. आयातकों/उपयोगकर्ताओं और उनके संघों द्वारा भागीदारी

- i. नियम 6(4) के अनुसार, भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को भी प्रश्नावली भेजी गई थी: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड; कृषि रसायन; बीएएसएफ इंडिया; और अमिश क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड।
- ii. जवाब में, निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने आयातक/उपयोगकर्ता प्रश्नावली का जवाब दायर किया: (1) झोंगशान क्रॉप साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; और (2) टेफ्रा बायोसाइंस एलएलपी।

7. पंजीकृत हितधारक

- i. निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितधारकों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितधारकों को अपनी सभी प्रस्तुतियों की गैर-गोपनीय प्रति अन्य सभी हितधारकों को वितरित करने का निर्देश दिया गया था।

8. मौखिक सुनवाई

- i. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 20 मई 2026 को आयोजित एक सुनवाई में हितधारकों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित प्रस्तुतीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया, उसके बाद यदि कोई हो तो जवाबी प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

9. आगे की प्रक्रिया

- i. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों, जिन्होंने जवाब नहीं दिया है, या इस जांच से प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है, को गैर-सहयोगी माना गया है।
- ii. नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितधारक ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक जानकारी तक पहुंचने से इनकार कर दिया है, या अन्यथा समय पर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, ऐसे पक्षों को गैर-सहयोगी माना गया है, और निष्कर्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज किए गए हैं।
- iii. नियम 7 के अनुसार, हितधारकों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की ऐसी गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां आवश्यक समझा गया, वहाँ गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया और अन्य हितधारकों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को उसकी पर्याप्त गैर-गोपनीय प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
- iv. गैर-हानिकारक मूल्य भारत में घरेलू समान लेख की इष्टतम उत्पादन लागत और बिक्री लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमों के अनुलग्नक III में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है, जैसा कि नियम 29(2) के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है।
- v. सभी हितधारकों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सभी जानकारियों पर, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक पाए गए हैं, विचार किया गया है।

- vi. जांच के ज़रूरी तथ्यों वाला एक डिस्कलोज़र स्टेटमेंट (जिसके आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकाला गया) 20 अगस्त 2026 को संबंधित पक्षों को जारी किया गया था और उन्हें इस पर अपनी राय देने के लिए 26 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम निष्कर्ष की सूचना में संबंधित पक्षों द्वारा दी गई जानकारी, उनकी दलीलों और डिस्कलोज़र स्टेटमेंट पर उनकी टिप्पणियों पर विचार किया गया है—बशर्ते वे प्रासंगिक हों, दोहराव वाली न हों और सबूतों के साथ हों।
- vii. इस प्रकटीकरण विवरण में '***' उस सूचना को दर्शाता है जो किसी हितधारक द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है और नियमों के तहत ऐसी ही मानी गई है।
- viii. विषय जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 87.26 रुपये है। मूल जांच में मानी गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.52 रुपये थी।

ख. विभिन्न मुद्दों पर अन्य हितधारकों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

6. जांच के दौरान अन्य हितधारकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- i. उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि हालांकि उन्होंने 8 अप्रैल 2026 को हितधारक के रूप में पंजीकरण कराया था, लेकिन उनका पंजीकरण केवल 15 अप्रैल 2026 को पुष्ट किया गया था। तदनुसार, आवेदन की गैर-गोपनीय प्रति प्रभावी रूप से केवल 15 अप्रैल 2026 को उपलब्ध कराई गई थी। नतीजतन, प्रश्नावली का जवाब दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 मई 2026 के बजाय 22 मई 2026 होनी चाहिए थी, और 7 जून 2026 तक समय विस्तार, विलंब के माफी के साथ, मांगा गया था।
- ii. वर्तमान अवशोषण जांच का आरंभ अस्थिर है क्योंकि आवेदक नियम 29 और 30 के तहत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहे। आवेदन अपूर्ण और अपर्याप्त साक्ष्य पर आधारित है और मुख्य रूप से निर्यात कीमतों में कथित गिरावट पर निर्भर करता है, बिना अन्य प्रासंगिक कारकों की जांच किए, जिनमें चीन में उत्पादन लागत में परिवर्तन, भारत में पुनर्विक्रय मूल्य, बाजार की स्थितियाँ और तीसरे देशों को निर्यात मूल्य शामिल हैं।
- iii. निर्यात कीमतों में मात्र गिरावट अवशोषण स्थापित नहीं करती है। नियम 29 के लिए यह जांच आवश्यक है कि क्या गिरावट एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण के कारण है, न कि उत्पादन लागत में कमी जैसे अन्य कारकों के कारण। वर्तमान मामले में, चीन में उत्पादन लागत में कोई प्रदर्शित कमी नहीं हुई है, न ही आवेदकों ने भारत में पुनर्विक्रय मूल्य या चीन में उत्पादन लागत से संबंधित डेटा प्रस्तुत किया है। नियम 29 के विपरीत घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत पर निर्भरता है।
- iv. आवेदक आवेदन में भरोसा किए गए निर्यात मूल्य डेटा, आयात मात्रा डेटा और लागत सूचना के स्रोत और आधार का खुलासा करने में विफल रहे हैं। निर्यात मूल्य डेटा संपूर्ण अवशोषण अवधि को कवर नहीं करता है और उत्पादन लागत में कथित परिवर्तन साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।
- v. आवेदकों द्वारा भरोसा किए गए तीसरे देशों को निर्यात मूल्य के साक्ष्य में केवल दो चीनी निर्यातकों से संबंधित चयनित चालान शामिल हैं और ये वास्तविक निर्यात, डिलीवरी या भुगतान के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। ऐसे चालान संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए हैं और इसलिए अवशोषण जांच का आधार नहीं बन सकते हैं।
- vi. भारत को निर्यात कीमतों में कथित गिरावट तीसरे देशों को निर्यात कीमतों में गिरावट के अनुरूप है और इसलिए यह अवशोषण स्थापित नहीं करती है। इसके अलावा, एक बार लागू एंटी-डंपिंग शुल्क और न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) पर विचार करने पर, मूल जांच अवधि की तुलना में भारत को निर्यात कीमतों में वास्तव में वृद्धि हुई है।
- vii. घरेलू उद्योग ने पूरी अवशोषण अवधि के दौरान एमआईपी संरक्षण का आनंद लेना जारी रखा है, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया है। अवशोषण अवधि के दौरान कथित 71 मीट्रिक टन आयात में से,

लगभग 56 मीट्रिक टन (लगभग 80%) 15 अमेरिकी डॉलर/किग्रा से अधिक कीमतों पर आयात किए गए थे, जो दर्शाता है कि अधिकांश आयात को अवशोषित आयात नहीं माना जा सकता है।

- viii. नियम 29 केवल एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद लागू होता है। इसलिए, प्राधिकारी के पास 8 मई 2025 से पहले किए गए आयात की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। प्रस्तावित नौ-माही पीओआई में शुल्क-पूर्व अवधि को अनुचित रूप से शामिल किया गया है, जिससे शुल्क-पश्चात् केवल चार महीने का डेटा बचता है, जो किसी सार्थक अवशोषण विश्लेषण के लिए अपर्याप्त है।
- ix. हालांकि नियम 29 एक विशिष्ट पीओआई निर्धारित नहीं करता है, लेकिन प्राधिकारी का विवेक असीमित नहीं है। पीओआई का निर्धारण नियम 5(3ए)(ii) द्वारा निर्देशित होना चाहिए, जो एक सामान्य बारह-माही पीओआई की परिकल्पना करता है और किसी भी विचलन के लिए दर्ज किए गए कारणों की आवश्यकता होती है, जैसा कि कल्याणी स्टील्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में मान्यता प्राप्त है।
- x. आवेदकों ने स्वयं नौ-माही पीओआई का प्रस्ताव रखा था, जिसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। हालाँकि, नियम 29 के तहत वर्तमान जांच अवधि की तुलना मूल जांच अवधि से करने का कोई कानूनी आधार नहीं है, और कराधान कानूनों की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए, बिना नियम में ऐसी आवश्यकताओं को पढ़े जो मौजूद नहीं हैं।
- xi. आवेदक यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क अप्रभावी हो गया है। आवेदकों के अपने डेटा के अनुसार, एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद भारत में केवल लगभग 56 मीट्रिक टन आयात हुआ, जिसमें से केवल लगभग 10 मीट्रिक टन कथित तौर पर कम कीमतों पर आयात किए गए थे। ऐसी नगण्य मात्राएँ नियम 29 के तहत शुल्क अवशोषण स्थापित नहीं कर सकती हैं।
- xii. एंटी-डंपिंग शुल्क के रूप में संशोधन का अनुरोध नियम 29(2) द्वारा समर्थित नहीं है। आवेदकों ने न तो यह उचित ठहराया है कि संशोधन क्यों आवश्यक है और न ही शुल्क के संशोधित रूप को निर्दिष्ट किया है। कोई भी संशोधन प्राधिकारी के स्वतंत्र उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए और एमआईपी की समाप्ति के बारे में आवेदकों की आशंका पर आधारित नहीं हो सकता है, क्योंकि एमआईपी और एंटी-डंपिंग शुल्क अलग-अलग और परस्पर अनन्य व्यापार उपचारात्मक उपाय हैं।
- xiii. एक अवशोषण समीक्षा का दायरा मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क की प्रभावशीलता को बहाल करने तक सीमित है। यह शुल्क के रूप या संरचना पर पुनर्विचार की अनुमति नहीं देता है, जो केवल एक उचित मध्य-अवधि या सूर्यास्त समीक्षा में ही किया जा सकता है।
- xiv. आवेदक एंटी-डंपिंग शुल्क के पूर्वव्यापी संशोधन को उचित ठहराने में विफल रहे हैं।
- xv. अधिसूचित एमआईपी से नीचे कोई भी आयात सीमा शुल्क या डीजीएफटी प्रवर्तन में कमियों को इंगित करता है, न कि एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण को। एमआईपी का प्रवर्तन सीमा शुल्क अधिकारियों और डीजीएफटी के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे अवशोषण कार्यवाही के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता है।
- xvi. आवेदकों ने नियम 7 का उल्लंघन किया है, भारत और तीसरे देशों को निर्यात कीमतों, खरीद विवरण, भूमि मूल्य गणना, शुद्ध निर्यात मूल्य, सामान्य मूल्य, डंपिंग मार्जिन, चोट मार्जिन और मूल जांच में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा करके, जिससे हितधारकों को सार्थक बचाव करने से रोका गया।
- xvii. यूपीएल घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र नहीं है। आवेदकों ने आवेदकों के साथ अपने संबंध का खुलासा किए बिना हांगकांग और यूईई में स्थित यूपीएल संस्थाओं से जुड़े चालानों पर भरोसा किया। आवेदक स्वयं विषय वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हो सकते हैं।

- xviii. आयातकों से अंतरिम मूल्यांकन और गारंटी का अनुरोध अनुचित है, क्योंकि यह वैध व्यापार को बाधित करेगा, अनुपालन बोझ बढ़ाएगा और आवेदन स्वयं अपर्याप्त साक्ष्य पर आधारित होने के बावजूद बाजार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
- xix. अवशोषण कार्यवाही निर्यातक-विशिष्ट होती है और प्रत्येक निर्यातक के आचरण का उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन आवश्यक है। जिन निर्यातकों ने एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद अपनी निर्यात कीमतों में कमी नहीं की है, या जिन्होंने प्रासंगिक अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया है, उन्हें केवल इस आधार पर बड़े हुए अवशोषण शुल्कों के अधीन नहीं किया जा सकता है कि अन्य निर्यातकों ने कथित तौर पर शुल्क को अवशोषित कर लिया है।
- xx. एंटी-डंपिंग शुल्कों में कोई भी वृद्धि या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर डाउनस्ट्रीम उद्योगों और उपयोगकर्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, जिससे इनपुट लागत बढ़ेगी, घरेलू और निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता कम होगी, और अंततः अंतिम उपभोक्ताओं, विशेष रूप से किसानों के लिए लागत बढ़ेगी।

ग. विभिन्न मुद्दों पर घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

7. जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद ग्लूफोसिनेट और इसके लवण हैं, तकनीकी और फॉर्मूलेशन दोनों रूपों में। हालांकि सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण और एचएस कोड समय के साथ बदल गए हैं, विचाराधीन उत्पाद का दायरा अपरिवर्तित रहा है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद के आयात एंटी-डंपिंग शुल्क और एमआईपी दोनों उपायों के अधीन रहे हैं। लगातार एमआईपी अधिसूचनाएँ, जिनका समापन 13 अप्रैल 2026 की अधिसूचना में हुआ, एमआईपी के दायरे को एंटी-डंपिंग शुल्क के साथ संरेखित करती हैं और स्पष्ट रूप से एंटी-डंपिंग शुल्क को कारक बनाती हैं, जो दर्शाता है कि अकेले मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क हानिकारक कीमतों पर आयात को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है।
- iii. हितधारक निर्धारित समय सीमा के भीतर गोपनीयता टिप्पणियाँ और प्रश्नावली का जवाब दाखिल करके प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहे। विस्तार के अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा चूक बताए जाने के बाद देरी से किए गए थे और इसलिए प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन को ठीक नहीं कर सकते हैं।
- iv. जांच पूरी करने के लिए प्राधिकारी की आंतरिक समय-सीमा हितधारकों को निर्धारित समय-सीमा से परे विस्तार मांगने का कोई अधिकार नहीं देती है।
- v. आर्थिक हित प्रश्नावली अवशोषण जांच में अप्रासंगिक है। नियम 29 के तहत कार्यवाही इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या निर्यातकों ने एंटी-डंपिंग शुल्क को अवशोषित किया है और मूल जांच में पहले से निर्धारित डंपिंग, चोट, कारणात्मक संबंध, घरेलू उद्योग या सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दों को फिर से नहीं खोलती है।
- vi. एंटी-डंपिंग शुल्क की निरंतरता और प्रभावी प्रवर्तन सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं है। घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, उसने महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, रोजगार सृजित किया है और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान दिया है। इसके अलावा, एंटी-डंपिंग शुल्क से फॉर्मूलेशन की एक बोतल की लागत में केवल लगभग 35-36 रुपये की वृद्धि होगी, जो एक एकड़ खेती के लिए पर्याप्त है, जिसका किसानों पर नगण्य प्रभाव पड़ता है।
- vii. नियम 29 के लिए प्राधिकारी को यह जांचना आवश्यक है कि क्या निर्यातकों ने उत्पादन लागत में संगत कमी के बिना निर्यात कीमतों में कमी की है, जिससे मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क अप्रभावी हो गया है। नियम 29(2) केवल पहले से निर्धारित सामान्य मूल्य और चोट मापदंडों के

समायोजन की अनुमति देता है और सामान्य मूल्य, चोट या चीन की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के ताजा निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती है।

- viii. मूल जांच में निर्धारित निर्यात मूल्य *** अमेरिकी डॉलर/किग्रा था, जबकि अवशोषण अवधि के दौरान औसत एफओबी निर्यात मूल्य घटकर *** अमेरिकी डॉलर/किग्रा हो गया, जो एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बावजूद लगभग 44% की गिरावट दर्शाता है।
- ix. आवेदकों ने चीन सीमा शुल्क निर्यात डेटा से प्राप्त वास्तविक निर्यात कीमतों पर भरोसा किया। चूंकि भारत में आयात एमआईपी के अधीन थे, भारतीय सीमा शुल्क आयात मूल्य एमआईपी अनुपालन द्वारा कृत्रिम रूप से प्रभावित थे और इसलिए निर्यातकों के वास्तविक मूल्य निर्धारण व्यवहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लेन-देन-वार निर्यात डेटा लगातार लगभग 5.78-5.79 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की कीमतों को दर्शाता है।
- x. निर्यात कीमतों में गिरावट उत्पादन लागत में किसी भी अनुरूप कमी से स्पष्ट नहीं होती है। जबकि कच्चे माल की लागत में केवल लगभग 100 रुपये/किग्रा की कमी आई, निर्यात कीमतों में लगभग 335 रुपये/किग्रा की कमी आई। भाग लेने वाले निर्यातकों ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया और न ही उत्पादन लागत में कोई संगत कमी स्थापित की।
- xi. यह तर्क कि नियम 29 संतुष्ट नहीं है क्योंकि तीसरे देशों को निर्यात कीमतों में भी कमी आई है, गलत है। धारा 9ए(1बी) और नियम 29 'या' शब्द का उपयोग करते हैं, जिससे प्रत्येक शर्त स्वतंत्र हो जाती है। एक बार निर्यात कीमतों में बिना उत्पादन लागत में संगत कमी के कमी आने पर, अवशोषण स्थापित हो जाता है।
- xii. आवेदकों ने सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी पर भरोसा किया, जिसमें चीन सीमा शुल्क डेटा, लेन-देन-वार निर्यात कीमतें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित कच्चे माल की कीमतें, तीसरे देशों को निर्यात डेटा और खरीद चालान शामिल हैं। घरेलू उत्पादकों से निर्यातकों के आंतरिक लागत रिकॉर्ड या भारत में पुनर्विक्रय मूल्य रखने की उचित रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- xiii. आवेदकों ने केवल कच्चे माल की लागत पर भरोसा नहीं किया है। उनका दावा निर्यात कीमतों, आयात मात्राओं, उत्पादन लागत और संपूर्ण अवशोषण अवधि को कवर करने वाले अन्य पुष्टिकारी साक्ष्यों पर आधारित है।
- xiv. भाग लेने वाले निर्यातकों ने स्वयं निर्यात कीमतों में गिरावट के अनुरूप अपनी उत्पादन लागत में किसी भी कमी को प्रदर्शित करने वाला साक्ष्य नहीं रखा। नतीजतन, उनके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है।
- xv. नियम 29(2) प्राधिकारी को एंटी-डंपिंग शुल्क के रूप, आधार और मात्रा को संशोधित करने के लिए स्पष्ट रूप से सशक्त बनाता है। चूंकि डंपिंग और चोट दोनों मार्जिन बढ़ गए हैं और भूमि मूल्य समायोजित गैर-हानिकारक मूल्य से नीचे बना हुआ है, मौजूदा उपाय में संशोधन उचित है।
- xvi. संशोधन का अनुरोध पूरी तरह से शुल्क अवशोषण के साक्ष्य पर आधारित है, न कि एमआईपी के अस्तित्व या समाप्ति पर। एमआईपी की बाढ़ की निरंतरता, जबकि स्पष्ट रूप से एंटी-डंपिंग शुल्क को कारक बनाती है, यह भी दर्शाती है कि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क अपने इच्छित उपचारात्मक प्रभाव को प्राप्त नहीं कर पाया है।
- xvii. मूल जांच के दौरान घरेलू उद्योग ने स्वयं एमआईपी के अस्तित्व के कारण बेंचमार्क-रूप शुल्कों का अनुरोध किया था। बाढ़ के नियामक विकास शुल्क के रूप और मात्रा दोनों में संशोधन की आवश्यकता को पुष्ट करते हैं।
- xviii. गोपनीयता के संबंध में आपत्तियाँ देरी से उठाई गई हैं। किसी भी स्थिति में, गोपनीय उपचार केवल व्यावसायिक-संवेदनशील जानकारी के लिए दावा किया गया है। सार्थक गैर-गोपनीय सारांश और अनुक्रमित गणना व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार प्रदान की गई थी, और हितधारक उन्हें हुई किसी भी वास्तविक हानि की पहचान करने में विफल रहे हैं।

- xix. यूपीएल घरेलू उत्पादक के रूप में पात्र बना हुआ है। हितधारकों द्वारा भरोसा किए गए लेन-देन विदेशी संबद्ध संस्थाओं द्वारा की गई खरीद से संबंधित हैं, न कि यूपीएल द्वारा भारत में आयात से। किसी भी स्थिति में, स्थिति मूल जांच में निर्णायक रूप से निर्धारित की गई थी और इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है।
- xx. नियम 31 स्पष्ट रूप से एक बार अवशोषण स्थापित हो जाने पर आरंभ की तारीख से किसी भी संशोधित एंटी-डंपिंग शुल्क के पूर्वव्यापी आवेदन का अधिकार देता है।
- xxi. नियम 29(3) जांच अवधि निर्धारित नहीं करता है। तदनुसार, प्राधिकारी द्वारा चुनी गई अवशोषण अवधि, जिसमें शुल्क-पश्चात् लेन-देन शामिल हैं, नियमों के अनुरूप है।
- xxii. एंटी-एब्जॉर्प्शन अवधि के दौरान लागू निर्यात कीमतों की तुलना मूल जांच में तय की गई कीमतों से करना नियम 29 का एक ज़रूरी हिस्सा है। यह अथॉरिटी की पिछली एंटी-एब्जॉर्प्शन जांचों और यूरोपियन कमीशन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप भी है।
- xxiii. एंटी-एब्जॉर्प्शन जांच में आयात की मात्रा निर्णायक नहीं होती है। आयात की कम मात्रा भी यह दिखा सकती है कि निर्यातकों ने एंटी-डंपिंग झूठी को खुद वहन किया है और भविष्य में नुकसान पहुंचाने वाले आयात की संभावना का संकेत दे सकती है।
- xxiv. उत्पादन लागत में कोई कमी किए बिना निर्यात कीमतों में भारी गिरावट को देखते हुए, मौजूदा एंटी-डंपिंग झूठी को चीनी निर्यातकों ने खुद वहन कर लिया है और अब इससे वह सुधारात्मक असर नहीं मिल रहा है जिसके लिए इसे लागू किया गया था। इसलिए, अथॉरिटी को नियम 29(2) के तहत एंटी-डंपिंग झूठी के स्वरूप, आधार और मात्रा में बदलाव करना चाहिए।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. चूंकि वर्तमान जांच लागू एंटी-डंपिंग शुल्क की अवशोषण समीक्षा है, विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में परिभाषित के अनुरूप ही रहेगा। मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्ष एफ. सं. 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी 2025 के माध्यम से निर्धारित विचाराधीन उत्पाद का दायरा, जो एंटी-डंपिंग शुल्क के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित है:

"18. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा ग्लूफोसिनेट और इसके लवण हैं, तकनीकी और फॉर्मूलेशन दोनों रूपों में।"

9. ग्लूफोसिनेट एक शाकनाशी है जो खरपतवारों की व्यापक स्पेक्ट्रम को नियंत्रित करने में अपनी प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। इसका सक्रिय घटक पौधे की कुछ आवश्यक अमीनो एसिड का उत्पादन करने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण का निषेध और उसके बाद पौधे की मृत्यु हो जाती है। यह ऑर्गेनोफॉस्फोरस रासायनिक परिवार से संबंधित एक फॉस्फिनिक एसिड है, जो शाकनाशियों के किसी अन्य रासायनिक वर्ग से अलग है।
10. विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, कोड 38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 और 38089999 पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
11. प्राधिकारी ने नोट किया कि वर्तमान जांच एक अवशोषण जांच है, और इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या निर्यात मूल्य उत्पादन लागत के अनुरूप रहा है। किसी भी हितधारक ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर कोई प्रस्तुति नहीं दी है, न ही किसी हितधारक ने दावा किया है कि मूल जांच में निर्यात किए गए उत्पाद और वर्तमान जांच में निर्यात किए गए उत्पाद में कोई अंतर है। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तु को चीन जनवादी गणराज्य से आयातित उत्पाद के 'समान लेख' के रूप में माना जाता है, और प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद या समान-लेख के दायरे के मुद्दे की आगे जांच करना आवश्यक नहीं समझता है।

विविध मुद्दे, समयबद्धता, स्थिति और गोपनीयता

12. विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गैर-गोपनीय प्रति नियम 6(7) और व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के अनुसार सभी हितधारकों को उपलब्ध कराई गई थी। नियमों का नियम 7 निम्नलिखित प्रावधान करता है:

"(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7) में किसी भी बात के होते हुए भी ... उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ, या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर नामित प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी, नामित प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, ऐसी ही मानी जाएगी और ऐसी कोई जानकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) नामित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है ... (3) ... यदि नामित प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है ... तो वह ऐसी जानकारी को नजरअंदाज कर सकता है।"

13. प्राधिकारी ने गोपनीयता पर घरेलू उद्योग और अन्य हितधारकों की प्रस्तुतियों की जांच की है। आरंभ अधिसूचना ने सभी हितधारकों को गोपनीयता के दावों पर गैर-गोपनीय दस्तावेजों के वितरण से सात दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर टिप्पणियाँ देने का अवसर प्रदान किया। अन्य हितधारकों से निर्धारित समय के भीतर गोपनीयता पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, और आपत्तियाँ पहली बार मौखिक सुनवाई के बाद दायर लिखित प्रस्तुतियों में उठाई गईं। प्राधिकारी ने नोट किया कि गोपनीयता का दावा सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन, चोट मार्जिन, मूल्य समायोजन, बिक्री और खरीद दस्तावेज, तथा ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम जैसी सूचनाओं के संबंध में किया गया है, जो सभी व्यावसायिक-संवेदनशील जानकारी का गठन करती हैं। नियम 7 और प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा के अनुसार, और व्यापार सूचना सं. 10/2018 को ध्यान में रखते हुए, भारत-औसत सामान्य मूल्य, गैर-हानिकारक मूल्य, डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन जैसे संवेदनशील मापदंडों को श्रेणियों के रूप में प्रकट किया गया है। प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के दावे उचित हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद गैर-गोपनीय संस्करण हितधारकों को प्रस्तुत जानकारी के सार को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। गोपनीयता के दुरुपयोग का तर्क, तदनुसार, स्वीकार नहीं किया जाता है।
14. हितधारकों ने तर्क दिया कि प्रश्नावली का जवाब बाद की तारीख में देय था और समय विस्तार और विलंब की माफी मांगी। प्राधिकारी ने विस्तार के अनुरोध पर विचार किया और उसे स्वीकार कर लिया। तदनुसार, विस्तार के बाद दायर की गई प्रस्तुतियों पर, जहां तक प्रासंगिक हैं, योग्यता के आधार पर विचार किया गया है। चूंकि भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया और न ही बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दायर की, सत्यापनीय लागत और मूल्य डेटा उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, सामान्य मूल्य मूल जांच में अपनाई गई पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है, जैसा कि खंड E3 में चर्चा की गई है।
15. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि आवेदन प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं करता है, कि नियम 30(2) के तहत साक्ष्य अपर्याप्त हैं, और इसलिए आरंभ अस्थिर है। प्राधिकारी ने नोट किया कि नियम 30(2) के लिए आवेदन में नियम 29(1) में संदर्भित परिस्थितियों के अस्तित्व के संबंध में आरंभ को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने की आवश्यकता है। आवेदन में विषय वस्तु का लेन-देन-स्तरीय आयात डेटा, मूल जांच की तुलना में निर्यात कीमतों में गिरावट के साक्ष्य, कच्चे माल की कीमतों पर तृतीय-पक्ष डेटा और तीसरे देशों को निर्यात मूल्य, तथा पुनर्मूल्यांकित डंपिंग और चोट मार्जिन शामिल थे। प्राधिकारी ने स्वयं को प्रथम दृष्टया साक्ष्य की पर्याप्तता और यथेष्टता के बारे में संतुष्ट करते हुए, आरंभ अधिसूचना दिनांक 2 मार्च 2026 में अपने कारण दर्ज किए। आरंभ के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता का आकलन आरंभ के चरण में उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि अंतिम निर्धारण पर लागू मानक से। प्राधिकारी संतुष्ट है कि साक्ष्य आरंभ को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त थे, और तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।

16. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि यूपीएल, निर्यातकों से संबंधित या स्वयं पीयूसी के आयातक होने के कारण, घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने योग्य नहीं है। प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग की स्थिति और नियम 2(बी) के तहत उसकी पात्रता की मूल जांच में जांच और निर्धारण किया गया था। नियम 29 के तहत एक अवशोषण जांच दायरे में सीमित है, यह जांचने के लिए कि क्या निर्यातकों ने लागू एंटी-डंपिंग शुल्क को अवशोषित किया है, और यह स्थिति, समान-लेख, चोट और कारणात्मक संबंध जैसे मुद्दों को फिर से नहीं खोलती है जो मूल जांच में निर्धारित किए गए थे। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग ने कहा है कि यूपीएल ने चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है, और हितधारकों द्वारा भरोसा की गई खरीद भारत के बाहर स्थित संबद्ध संस्थाओं द्वारा की गई थी। प्राधिकारी वर्तमान कार्यवाही में घरेलू उद्योग की स्थिति की फिर से जांच करना आवश्यक नहीं समझता है, और तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है। प्राधिकारी उत्तरदायी आयातकों में से एक की व्यावसायिक प्रकृति और उसकी गतिविधियों की प्रकृति के बारे में घरेलू उद्योग की प्रस्तुति को भी समान रूप से नोट करता है। वर्तमान कार्यवाही में निर्धारण विषय देश के निर्यातकों के निर्यात मूल्य निर्धारण व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि रिकॉर्ड पर आयातकों की व्यावसायिक प्रकृति पर, और प्राधिकारी तदनुसार उस प्रस्तुति की जांच करना आवश्यक नहीं समझता है।
17. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि शुल्क के रूप में संशोधन और कोई भी पूर्वव्यापी आवेदन अवशोषण कार्यवाही के दायरे से बाहर होगा, कि मांगी गई राहत दंडात्मक और निर्यातक-अज्ञेय है, और वृद्धि उपयोगकर्ता उद्योग और किसानों के लिए हानिकारक होगी। प्राधिकारी ने नोट किया कि नियम 29(2) स्पष्ट रूप से प्राधिकारी को, अवशोषण स्थापित करने पर, शुल्क के रूप या आधार, या शुल्क की मात्रा, या दोनों में संशोधन की सिफारिश करने के लिए सशक्त बनाता है, और नियम 31 पूर्वव्यापी आवेदन के रूप में सिफारिश की अनुमति देता है। वर्तमान जांच नियम 29(2) के अनुसार डंपिंग और चोट मार्जिन के पुनर्निर्धारण तक सीमित है; किसी भी संशोधन की सीमा, रूप और आवेदन की तारीख अंतिम निष्कर्ष में प्राधिकारी की सिफारिश के मामले हैं, जो कम-शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए किए जाने हैं। जहां तक उपयोगकर्ता हित का संबंध है, सार्वजनिक हित के मुद्दों की मूल जांच में जांच की गई थी, और घरेलू उद्योग ने प्रदर्शित किया है कि शुल्क का अंतिम उपभोक्ता पर प्रति-इकाई प्रभाव नगण्य है। ये तर्क नीचे की जा रही अवशोषण की जांच से अलग नहीं होते हैं।

एंटी-डंपिंग शुल्क का अवशोषण

18. एंटी-डंपिंग नियमों का नियम 29(1) प्रावधान करता है कि एक एंटी-डंपिंग शुल्क तब अवशोषित माना जा सकता है जब निर्यात करने वाले देश से किसी लेख के निर्यात मूल्य एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद ऐसे लेख की उत्पादन लागत में किसी अनुरूप परिवर्तन के बिना कम हो जाते हैं, या भारत के अलावा अन्य देशों को ऐसे लेख के निर्यात मूल्य कम हो जाते हैं, या भारत में ऐसे लेख का पुनर्विक्रय मूल्य कम हो जाता है। "या" शब्द का उपयोग इसे स्पष्ट करता है कि भारत को निर्यात मूल्य में गिरावट के साथ तीनों शर्तों में से किसी एक की संतुष्टि अवशोषण स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। नीचे की गई जांच तदनुसार की जाती है।

अवशोषण अवधि के दौरान विषय वस्तु का लेन-देन-वार आयात

19. अवशोषण अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार डेटा विषय देश से विषय वस्तु के निम्नलिखित आयातों को दर्ज करता है।

क्रम संख्या	बीई दिनांक	सीटीएच	मात्रा (किग्रा)	निर्धारण योग्य मूल्य (₹)	CIF (₹/किग्रा)	CIF (\$/किग्रा)
1	***	38089390	15,000	***	***	15-16
2	***	38089399	5,000	***	***	5-6
3	***	38089399	23,000	***	***	15-16

4	***	38089399	23,000	***	***	15-16
कुल			66,000			

स्रोत: डीजी सिस्टम्स लेन-देन-वार डेटा। 87.26 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर की दर से परिवर्तित मूल्य।

20. अथॉरिटी ऊपर दिए गए डेटा से ये बातें नोट करती है। पहला, एब्जॉप्शन पीरियड के दौरान इम्पोर्ट किए गए संबंधित सामान की कुल मात्रा 66 मीट्रिक टन है। दूसरा, एस.एन. 1 पर मौजूद कंसाइनमेंट को 8 मई 2025 को एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू होने से पहले, *** अप्रैल 2025 को क्लियर किया गया था; ड्यूटी लागू होने के बाद की मात्रा 51 मीट्रिक टन है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात यह है कि एस.एन.1, 3 और 4 पर मौजूद कंसाइनमेंट मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस के आस-पास की सीआईएफ वैल्यू पर आए थे, जबकि एस.एन. 2 पर मौजूद 5 मीट्रिक टन का कंसाइनमेंट ऐसी सीआईएफ वैल्यू पर आया था जो अन्य कंसाइनमेंट के लेवल का लगभग 38% था। एस.एन.1, 3 और 4 पर मौजूद कंसाइनमेंट पार्टिसिपेट करने वाले एक्सपोर्टर से जवाब देने वाले इम्पोर्टर्स में से एक द्वारा इम्पोर्ट किए गए थे; एस.एन. 2 पर मौजूद कंसाइनमेंट ऐसे इम्पोर्टर द्वारा इम्पोर्ट किया गया था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और यह संबंधित देश के ऐसे एक्सपोर्टर से आया था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था।
21. चौथी बात, रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि संबंधित सामान से प्रोज्यूसर को जो असल कमाई हुई, वह उस कीमत से काफी कम थी जिस पर वे सामान भारत को एक्सपोर्ट किए गए और भारत में इम्पोर्ट के समय उनकी कीमत बताई गई। वेरिफिकेशन के जवाब में, शामिल पार्टियों ने प्रोज्यूसर के ग्रुप ट्रांसफर इनवॉइस पेश किए। इन इनवॉइस की पुष्टि प्रोज्यूसर के ईआरपी सिस्टम में उसी समय की गई एंटीज़ से होती है। इनसे पता चलता है कि प्रोज्यूसर, मेसर्स ज़ियांगशुई झोंगशान बायोसाइंस कंपनी लिमिटेड ने संबंधित एक्सपोर्टर, मेसर्स झेजियांग झोंगशान केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड (एक ग्रुप कंपनी) को ये सामान बेचे थे। इस बिक्री से 'एक्स-वर्क्स' आधार पर मिली रकम लगभग *** से *** USD प्रति किलोग्राम थी। उन्हीं सामानों के लिए संबंधित एक्सपोर्टर ने भारत को एक्सपोर्ट करने के वास्ते इनवॉइस बनाए और भारतीय कस्टम्स के सामने सीआईएफ आधार पर उनकी कीमत लगभग 15.0 से 15.2 USD प्रति किलोग्राम बताई। इसलिए, शामिल पार्टियों के अपने वेरिफाइड रिकॉर्ड के आधार पर, जिस कीमत पर प्रोज्यूसर ने वे सामान बेचे, वह भारत में इम्पोर्ट के समय बताई गई कीमत का लगभग 35% से 45% थी।
22. अथॉरिटी इस बात से वाकिफ़ है कि यह 'एक्स-वर्क्स' ट्रांज़ैक्शन (कारखाने से सीधे बिक्री का सौदा) एक ही ग्रुप की संबंधित कंपनियों के बीच हुआ है और यह अपने आप में 'आर्म्स-लेंथ प्राइस' (स्वतंत्र बाज़ार मूल्य) नहीं है जिसे सामान्य मूल्य या निर्यात मूल्य माना जा सके, और न ही इसे ऐसा माना गया है। हालाँकि, यह इसमें शामिल पार्टियों का अपना समकालीन और सत्यापित रिकॉर्ड है, और यह दो वजहों से महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि भारत में आयात के समय घोषित मूल्य को 'न्यूनतम आयात मूल्य' (एमआईपी) या उसके आस-पास बनाए रखा गया था, जबकि उत्पादक को असल में उससे काफी कम कीमत मिल रही थी; और, यह आवेदकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए स्वतंत्र 'चीन कस्टम्स' के निर्यात डेटा और एस.एन. 2 पर मौजूद एमआईपी से कम कीमत वाले कंसाइनमेंट (माल की खेप) से काफी हद तक मेल खाता है। इससे इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि एब्जॉप्शन पीरियड (कीमत सोखने की अवधि) के दौरान भारत में संबंधित सामान की प्रभावी कीमत घोषित आयात मूल्यों से काफी कम थी और लागू ड्यूटी (शुल्क) का सुधारात्मक असर कमज़ोर पड़ गया था।

न्यूनतम आयात मूल्य पर निर्भरता और वास्तविक निर्यात मूल्य

23. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि भारतीय सीमा शुल्क डेटा में परिलक्षित आयात मूल्यों में कोई गिरावट नहीं दिखती है, और घरेलू उद्योग ने पूरी अवशोषण अवधि के दौरान एमआईपी संरक्षण का आनंद लिया। प्राधिकारी ने नोट किया कि अधिनियम की धारा 9ए(1बी) के साथ पठित नियम 29 के

तहत एक अवशोषण जांच का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या निर्यातकों ने एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए शुल्क लगाए जाने के बाद अपने वास्तविक निर्यात मूल्यों में कमी की है। ऐसी जांच के लिए आवश्यक रूप से निर्यातकों द्वारा वसूले गए वास्तविक निर्यात मूल्यों का निर्धारण आवश्यक है, न कि अन्य नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए घोषित मूल्यों का। पैराग्राफ 19 से 21 में दर्ज कारणों के लिए, प्राधिकारी ने चीन सीमा शुल्क निर्यात डेटा द्वारा पुष्टि किए जाने पर, न्यूनतम आयात मूल्य के बंधन से मुक्त दाखिल हुए माल की कीमत को भारत को विषय वस्तु की वास्तविक निर्यात मूल्य निर्धारण के प्रतिनिधि के रूप में अपनाया है। एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) का मात्र अस्तित्व ही अंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण के निष्कर्ष को रोकता नहीं है।

24. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि एमआईपी से नीचे साफ किया गया कोई भी आयात सीमा शुल्क/डीजीएफटी प्रवर्तन का मामला है, न कि प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के भीतर अवशोषण का साक्ष्य। प्राधिकारी ने नोट किया कि डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित एमआईपी और अधिनियम की धारा 9ए के तहत लगाया गया एंटी-डंपिंग शुल्क अलग-अलग वैधानिक शासनों के तहत काम करने वाले अलग-अलग साधन हैं। एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण की जांच धारा 9ए(1बी) के साथ पठित नियम 29 के तहत प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है। वास्तविक निर्यात मूल्यों पर निर्भरता निर्यातकों के मूल्य निर्धारण व्यवहार की जांच के सीमित उद्देश्य के लिए है, और एमआईपी का प्रवर्तन नहीं है। तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।
25. प्राधिकारी ने भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा दायर वाणिज्यिक चालान और संबंधित सीमा शुल्क निर्यात घोषणाओं पर अलग से विचार किया है, जो ऊपर अपनाई गई कीमत से भौतिक रूप से ऊपर सीआईएफ आधार पर घोषित मूल्यों को दर्ज करते हैं। वे घोषित मूल्य पैराग्राफ 19 की तालिका के क्र.सं. 1, 3 और 4 पर माल के अनुरूप हैं, जो एमआईपी के क्षेत्र में साफ किए गए थे, और ऊपर दर्ज कारणों के लिए ऐसे घोषित मूल्य एक अलग नियामक आवश्यकता के अनुपालन को दर्शाते हैं, न कि वास्तविक निर्यात मूल्य निर्धारण व्यवहार को। भाग लेने वाले निर्यातकों ने अपनी उत्पादन लागत, या अपने तीसरे देशों को लेन-देन-वार निर्यात मूल्य रिकॉर्ड पर नहीं रखे हैं, और न ही उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया है; इसलिए उन्होंने प्राधिकारी के समक्ष कोई सत्यापनीय सामग्री नहीं रखी है जो अपनाई गई कीमत को विस्थापित कर सके।

उत्पादन लागत में गतिविधि

26. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत पर निर्भर नहीं किया जा सकता है, और नियम 29 के लिए निर्यात करने वाले देश में उत्पादन लागत की जांच आवश्यक है। प्राधिकारी ने नोट किया कि मूल जांच में, चीनी उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम करने वाला माना गया था। वर्तमान जांच में, भाग लेने वाले निर्यातकों ने न तो बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा किया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दायर की है। इसलिए प्राधिकारी यह जांचने के लिए निर्यातकों के लागत डेटा पर निर्भर रहने में असमर्थ है कि क्या निर्यात कीमतों में गिरावट उनकी उत्पादन लागत में किसी भी गिरावट के अनुरूप है। निर्यातकों से सत्यापनीय लागत जानकारी के अभाव में, और मूल जांच में अपनाई गई गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति के अनुरूप, प्राधिकारी ने उत्पादन लागत में परिवर्तन के लिए एक सरोगेट के रूप में विषय वस्तु के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कच्चे माल की वैश्विक स्तर पर प्रचलित कीमतों में गतिविधि की जांच की है। प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	जनवरी 2023-दिसंबर 2023	जनवरी 2025-सितंबर 2025
1	एसीटिक एसिड	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	84
2	एक्रोलिन टेक्रिकल	₹/किग्रा	***	***

	रुझान	सूचकांकित	100	98
3	अमोनिया घोल 24%	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	107
4	कॉस्टिक सोडा लाइ (32%)	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	102
5	हाइड्रोजन पाइपलाइन	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	101
6	तरल क्लोरीन पाइपलाइन	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	122
7	मैग्नीशियम टर्निंग्स	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	78
8	मेथनॉल	₹/किग्रा	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	112
9	मिथाइल क्लोराइड	₹/kg	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	88
10	फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड	₹/kg	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	80
11	सोडियम साइनाइड	₹/kg	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	87
12	ट्राइएथिल फॉस्फाइट	₹/kg	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	91
	कुल	₹/kg	***	***
	रुझान	सूचकांकित	100	93

27. यह देखा गया है कि प्रासंगिक कच्चे माल की कीमतों का कुल योग अवशोषण अवधि के दौरान लगभग 101 रुपये प्रति किग्रा (*** रुपये/किग्रा से *** रुपये/किग्रा तक) घट गया है, अर्थात् लगभग 7.4% की कमी।

भारत को निर्यात मूल्य में गतिविधि

28. यह जांचने के लिए कि क्या एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद निर्यात मूल्यों में कमी आई है, प्राधिकारी ने मूल जांच अवधि के दौरान भारत को विषय वस्तु के निर्यात मूल्य की तुलना पैराग्राफ 19 से 22 में निर्धारित अवशोषण अवधि के दौरान वास्तविक निर्यात मूल्य से की है। शुद्ध निर्यात मूल्य सीआईएफ मूल्य से नीचे दी गई कटौतियाँ करके प्राप्त किया गया है, ताकि मूल्य को कारखाना स्तर पर लाया जा सके।

क्रम संख्या	विवरण	माप की इकाई	₹/किग्रा	\$/किग्रा
1	CIF मूल्य	₹/किग्रा	***	***
2	घटाएँ: समुद्री माल भाड़ा	₹/किग्रा	***	***
3	घटाएँ: समुद्री बीमा @ 0.05%	₹/किग्रा	***	***
4	FOB मूल्य	₹/किग्रा	***	***
5	घटाएँ: कमीशन @ 3%	₹/किग्रा	***	***
6	घटाएँ: बैंक शुल्क @ 0.5%	₹/किग्रा	***	***
7	घटाएँ: बंदरगाह व्यय @ 0.5%	₹/किग्रा	***	***
8	घटाएँ: हैंडलिंग व्यय @ 0.5%	₹/किग्रा	***	***
9	शुद्ध निर्यात मूल्य	₹/किग्रा	***	***

विनिमय दर: 87.26 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर।

29. उपरोक्त आधार पर, अवशोषण अवधि के दौरान भारत को विषय वस्तु का शुद्ध निर्यात मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा की सीमा में है, जबकि मूल जांच में निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा की सीमा में था। एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद निर्यात मूल्य में तदनुसार लगभग 46% की गिरावट आई है। उपरोक्त गणना में लागू *** प्रति मीट्रिक टन का समुद्री माल भाड़ा रिकॉर्ड पर मौजूद शिपिंग दस्तावेजों से निर्धारित किया गया है। अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि गिरावट, यदि कोई है, भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण है। प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यात मूल्य अमेरिकी डॉलर में उद्धृत है, और गिरावट अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में स्पष्ट है; इसलिए, गिरावट को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि निर्यात मूल्य एक ही मुद्रा में व्यक्त और तुलना की जाती है, निर्यातक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि गिरावट रुपये के अवमूल्यन का परिणाम है।

तीसरे देशों को निर्यात मूल्य

30. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि भारत को निर्यात मूल्य में गिरावट तीसरे देशों को निर्यात मूल्य में गिरावट के अनुरूप है, और इसलिए नियम 29 संतुष्ट नहीं है। प्राधिकारी ने नोट किया कि, पहला, भाग लेने वाले निर्यातकों ने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए तीसरे देशों को कोई लेन-देन-वार निर्यात डेटा रिकॉर्ड पर नहीं रखा है, और तर्क तदनुसार अप्रमाणित रहता है। दूसरा, और किसी भी स्थिति में, नियम 29(1) वियोज्य है: भारत को निर्यात मूल्य में गिरावट के साथ उत्पादन लागत में अनुरूप परिवर्तन की अनुपस्थिति, अपने आप में, अवशोषण स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, तीसरे देशों की कीमतों की गतिविधि से स्वतंत्र। जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, भारत को निर्यात मूल्य में लगभग 46% की गिरावट आई, जबकि प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में केवल लगभग 7.4% की कमी आई। इसलिए निर्यात मूल्य में गिरावट उत्पादन लागत में परिवर्तन के अनुरूप नहीं है, और नियम 29(1) के पहले खंड के तहत शर्त पूरी होती है। तर्क तदनुसार स्वीकार नहीं किया जाता है।
31. प्राधिकारी ने अवशोषण अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद का वास्तविक लेन-देन मूल्य क्या था, इसकी जांच की है। तीन स्वतंत्र स्रोत एकत्रित होते हैं: आवेदक के चीनी उत्पादकों और व्यापारियों के चालान, जो 5.50-6.10 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की सीमा में एफओबी मूल्य दिखाते हैं; आवेदक द्वारा भरोसा किया गया चीनी सीमा शुल्क निर्यात डेटा, जो 5.50-6.00 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की सीमा में एक भारित औसत एफओबी मूल्य दिखाता है; और भाग लेने वाले निर्यातक की

अपनी परिशिष्ट-1, जो 5.50–6.00 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की सीमा में घरेलू बाजार प्राप्ति की रिपोर्ट करती है। निर्यातक ने स्वयं कहा है कि चीन में बेचा गया लेख और भारत को निर्यात किया गया लेख समान गुणवत्ता और पैकिंग के हैं, और विशेषताओं या बिक्री की शर्तों में किसी अंतर का साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्राधिकारी तदनुसार इसे स्थापित मानता है कि अवशोषण अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद 5.50–6.10 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की सीमा में बेचा गया था। यह निष्कर्ष केवल मूल्य स्तर से संबंधित है; सामान्य मूल्य मूल जांच में अपनाए गए आधार पर जारी है; निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार से इनकार कर दिया है।

भारत में पुनर्विक्रय मूल्य

32. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि आवेदकों ने भारत में विषय वस्तु के पुनर्विक्रय मूल्यों से संबंधित कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि, नियम 29(1) का पहला खंड ऊपर दर्ज कारणों के लिए संतुष्ट होने के कारण, और प्रावधान वियोज्य होने के कारण, यह आवश्यक नहीं है कि पुनर्विक्रय-मूल्य खंड स्वतंत्र रूप से संतुष्ट हो। प्राधिकारी ने फिर भी रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच की है। दो आयातकों, अर्थात् झोंगशान क्रॉप साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टेफ्रा बायोसाइंस एलएलपी ने भारत में विषय वस्तु के आयात और पुनर्विक्रय के विवरण वाले प्रश्नावली का जवाब दायर किया है। दायर किए गए डेटा पर, अवशोषण अवधि के दौरान भारत में आयातित विषय वस्तु के पुनर्विक्रय मूल्य संबंधित भूमि मूल्यों से ऊपर हैं, और अवशोषण अवधि में पुनर्विक्रय मूल्यों में कोई गिरावट का रुझान नहीं दिखता है। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद पुनर्विक्रय डेटा एमआईपी के क्षेत्र में साफ किए गए माल से संबंधित है, और पैराग्राफ 19 की तालिका के क्र.सं. 2 पर माल तक विस्तारित नहीं है, जिसके आयातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

जांच अवधि और आयात की मात्रा

33. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि नियम 29 को केवल शुल्क लगाए जाने के बाद ही लागू किया जा सकता है, और 9-माही अवशोषण अवधि के भीतर शुल्क-पूर्व अवधि को शामिल करना एक अधिकार क्षेत्रीय त्रुटि है। प्राधिकारी ने नोट किया कि अवशोषण का विश्लेषण 8 मई 2025 को एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद निर्यातकों के वास्तविक निर्यात मूल्य निर्धारण व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसा कि पैराग्राफ 19 की तालिका से पता चलता है, शुद्ध निर्यात मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा किया गया माल जुलाई 2025 को साफ किया गया था, अर्थात् शुल्क लगाए जाने के बाद; और शुल्क-पश्चात् आयात की मात्रा कुल 66 मीट्रिक टन में से 51 मीट्रिक टन है। इसलिए निर्यात मूल्य में गिरावट का निष्कर्ष शुल्क-पूर्व लेन-देन पर निर्भर नहीं है, और अवशोषण की वर्णनात्मक अवधि के भीतर पहले के महीनों को शामिल करना विश्लेषण को दोषपूर्ण नहीं बनाता है। तर्क, तदनुसार, स्वीकार नहीं किया जाता है।
34. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि अवशोषण-अवधि की कीमतों की मूल पीओआई से तुलना करने का कोई कानूनी आधार नहीं है, और 9-माही अवधि मनमानी है क्योंकि नियम 5(3ए)(ii) एक सामान्य 12-माही पीओआई निर्धारित करता है। प्राधिकारी ने नोट किया कि नियम 29(1) स्वयं "एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद" निर्यात मूल्य की तुलना उस आधार से करने की परिकल्पना करता है जिस पर शुल्क मूल रूप से निर्धारित किया गया था; ऐसी तुलना के लिए आवश्यक रूप से मूल जांच अवधि के निर्यात मूल्य को बेंचमार्क के रूप में आवश्यकता होती है, क्योंकि लागू शुल्क उस अवधि में प्रचलित स्थितियों पर निर्धारित किया गया था। जहां तक जांच अवधि का संबंध है, नियम 29 एक अवशोषण समीक्षा के लिए एक निश्चित पीओआई निर्धारित नहीं करता है; अवधि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जा सकती है, और प्राधिकारी ने 9-माही अवधि अपनाने के अपने कारण आरंभ अधिसूचना में दर्ज किए। नियम 5(3ए)(ii) मूल जांच के लिए जांच अवधि को नियंत्रित करता है और अपने आप में नियम 29 के तहत उपलब्ध विवेक को सीमित नहीं करता है। तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।

35. अन्य हितधारकों ने तर्क दिया है कि कम कीमत पर आयात की मात्रा इतनी कम है कि यह स्थापित नहीं कर सकती कि शुल्क अप्रभावी हो गया था। प्राधिकारी खुलकर स्थिति दर्ज करता है: शुल्क लगाए जाने के बाद आयातित 51 मीट्रिक टन में से, 5 मीट्रिक टन, या लगभग 10%, कम कीमत पर दाखिल हुआ, शेष न्यूनतम आयात मूल्य के क्षेत्र में साफ किया गया। प्राधिकारी नोट करता है, हालांकि, नियम 29 निर्यातकों के मूल्य निर्धारण व्यवहार पर और क्या ऐसा व्यवहार एंटी-डंपिंग शुल्क को अप्रभावी बनाता है, पर निर्देशित है, न कि आयात की किसी सीमा मात्रा पर; न तो धारा 9ए(1बी) और न ही नियम 29 कोई न्यूनतम मात्रा निर्धारित करता है। क्र.सं. 2 पर माल का महत्व उसकी मात्रा में नहीं है, बल्कि इस तथ्य में है कि यह अवशोषण अवधि के दौरान एकमात्र माल है जो न्यूनतम आयात मूल्य के बंधन से मुक्त दाखिल हुआ, और यह ऐसी कीमत पर दाखिल हुआ जिस पर 2,998 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन का एंटी-डंपिंग शुल्क काफी हद तक निष्प्रभावी हो जाता है, जो कि भौतिक रूप से बड़ी मात्रा को कवर करने वाले चीन सीमा शुल्क निर्यात डेटा के अनुरूप है। प्राधिकारी के विचार में उस कीमत पर आयात की मात्रा, निर्यातकों के मूल्य निर्धारण व्यवहार के बजाय लागू एमआईपी का एक कार्य है, और समवर्ती उपाय में किसी भी ढील पर बड़े हुए हानिकारक आयातों की संभावना का संकेत है। तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।

अवशोषण पर विश्लेषण

36. उपरोक्त के आलोक में, प्राधिकारी नोट करता है कि जबकि कच्चे माल की कीमतों (लगभग 7.4% तक) और सरोगेट उत्पादन लागत में मामूली कमी आई है, भारत को विषय वस्तु का निर्यात मूल्य एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद लगभग 46% कम हो गया है। इस प्रकार निर्यात मूल्य में गिरावट उत्पादन लागत में परिवर्तन से कहीं अधिक है, और उसके अनुरूप नहीं है। नीचे दी गई तालिका निर्यातकों द्वारा अवशोषण की डिग्री का सारांश प्रस्तुत करती है।

क्रम संख्या	विवरण	माप की इकाई	पीओआई – ओआई	पीओआई – एबी
1	भारत को शुद्ध निर्यात मूल्य (रुझान, सूचकांकित)	सूचकांकित	100	54
2	कच्चे माल की लागत (रुझान, सूचकांकित)	सूचकांकित	100	93

37. प्राधिकारी, तदनुसार, नोट करता है कि विषय देश से विषय वस्तु का निर्यात मूल्य एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद उत्पादन लागत में किसी अनुरूप परिवर्तन के बिना कम हो गया है। नियम 29(1) के तहत अवशोषण की शर्त इसलिए पूरी होती है। प्राधिकारी ने नियम 29(2) के अनुसार डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन किया है, जैसा कि नीचे खंड E.3 में निर्धारित किया गया है।

डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन

38. एंटी-डंपिंग नियमों का नियम 29(2) निम्नलिखित प्रावधान करता है:

"(2) जहां एंटी-डंपिंग शुल्क के अधीन कोई लेख ऐसी कीमत पर या ऐसी शर्तों के तहत भारत में आयात किया जाता है जिसे मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क का अवशोषण माना जाता है, और ऐसा शुल्क इस प्रकार अप्रभावी हो जाता है या हो सकता है, वहाँ नामित प्राधिकारी, समीक्षा करने के बाद, डंपिंग मार्जिन और चोट मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद एंटी-डंपिंग शुल्क के रूप या आधार, या एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा, या दोनों में संशोधन की सिफारिश कर सकता है, और पहले से निर्धारित सामान्य मूल्य और चोट में उचित परिवर्तन या समायोजन, यदि आवश्यक हो, क्रमशः नियम 10 और इन नियमों के अनुलग्नक III के प्रावधानों के अनुसार किए जा सकते हैं।"

39. प्राधिकारी ने नोट किया कि नियम 29(2) "पहले से निर्धारित सामान्य मूल्य और चोट में ... उचित परिवर्तन या समायोजन" करने की परिकल्पना करता है। इस शक्ति के प्रयोग में प्राधिकारी ने अवशोषण अवधि के लिए नियम 10 और क्रमशः अनुलग्नक III के अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया है। दोबारा आंकी गई गैर-हानिकारक मूल्य, शुरुआती जांच में तय गैर-हानिकारक मूल्य, से लगभग 14% कम है। इसकी मुख्य वजह कच्चे माल की लागत में आई कमी है, जो लगभग 19% है। चूंकि चीनी उत्पादकों ने मूल जांच के समय बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया था, और भाग लेने वाले निर्यातकों ने वर्तमान कार्यवाही में ऐसा उपचार का दावा नहीं किया है, निर्मित सामान्य मूल्य नियमों के अनुलग्नक-I के पैरा-7 के तहत मूल जांच में अपनाई गई पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को चोट का कोई ताजा निर्धारण नहीं किया है, मूल जांच का चोट निर्धारण अवशोषण समीक्षा में फिर से नहीं खोला जा रहा है।

40. अवशोषण अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकित निर्मित सामान्य मूल्य निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	पीओआई – ओआई	पीओआई – एबी
1	निर्मित सामान्य मूल्य	\$/किग्रा	***	***
2	विनिमय दर	₹/\$	83.52	87.26

41. अवशोषण अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकित गैर-हानिकारक मूल्य निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	पीओआई – ओआई	पीओआई – एबी
1	गैर-हानिकारक मूल्य	\$/किग्रा	***	***
2	विनिमय दर	₹/\$	83.52	87.26

42. पुनर्मूल्यांकित निर्मित सामान्य मूल्य और पैराग्राफ 27 में निर्धारित विषय वस्तु के शुद्ध निर्यात मूल्य पर विचार करते हुए, चीन जनवादी गणराज्य से विषय वस्तु के लिए डंपिंग मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	निर्मित सामान्य मूल्य (\$/किग्रा)	शुद्ध निर्यात मूल्य (\$/किग्रा)	डंपिंग मार्जिन (\$/किग्रा)	डंपिंग मार्जिन सीमा (%)
1	मूल अवधि	***	***	***	20–30%
2	अवशोषण अवधि	***	***	***	85–95%

43. यह देखा गया है कि भारत को शुद्ध निर्यात मूल्य मूल अवधि से अवशोषण अवधि तक काफी कम हो गया है, और शुद्ध निर्यात मूल्य में गिरावट पुनर्मूल्यांकित निर्मित सामान्य मूल्य में गिरावट से अधिक तीव्र है।

परिणामस्वरूप, डंपिंग मार्जिन मूल अवधि के दौरान 20–30% की सीमा से बढ़कर अवशोषण अवधि के दौरान 85–95% की सीमा तक पहुंच गया है, अर्थात् लगभग तीन गुना वृद्धि। अब निर्धारित डंपिंग मार्जिन उस राशि से *** अधिक है, जो स्थापित करता है कि लागू एंटी-डंपिंग शुल्क निर्यातकों द्वारा निर्यात मूल्य में कमी के माध्यम से अवशोषित कर लिया गया है और अब पाई गई डंपिंग की भरपाई नहीं करता है।

44. इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि डंपिंग मार्जिन बढ़ गया है।
45. विषय वस्तु के पुनर्मूल्यांकित गैर-हानिकारक मूल्य और भूमि मूल्य पर विचार करते हुए, चीन जनवादी गणराज्य से विषय वस्तु के लिए चोट मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	एनआईपी (\$/किग्रा)	उत्तरित मूल्य (\$/किग्रा)	क्षति मार्जिन (\$/किग्रा)	क्षति मार्जिन सीमा (%)
1	मूल अवधि	***	***	***	20–30%
2	अवशोषण अवधि	***	***	***	85–95%

46. यह देखा गया है कि विषय आयात का भूमि मूल्य मूल अवधि के दौरान *** अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा से घटकर अवशोषण अवधि के दौरान *** अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा हो गया है, जो लगभग 45% की कमी है, जबकि पुनर्मूल्यांकित गैर-हानिकारक मूल्य में लगभग 18% की कमी आई है। परिणामस्वरूप, चोट मार्जिन मूल अवधि के दौरान 20–30% की सीमा से बढ़कर अवशोषण अवधि के दौरान 85–95% की सीमा तक पहुंच गया है। विषय आयात का भूमि मूल्य लागू एंटी-डंपिंग शुल्क को ध्यान में रखने के बाद भी गैर-हानिकारक मूल्य से काफी नीचे बना हुआ है, जो पुष्टि करता है कि शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव कमजोर हो गया है।
47. आयात का भूमि मूल्य प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा के अनुसार, मूल्यांकन योग्य मूल्य के साथ-साथ लागू सीमा शुल्कों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
48. इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चोट का अंतर बढ़ गया है।

6. खुलासे के बाद की टिप्पणियाँ

च.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा दी गई जानकारी/टिप्पणियाँ

49. इच्छुक पक्षों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं।
- एक्सपोर्ट की कीमतों में गिरावट का कारण ग्लुफोसिनेट की कीमतों में वैश्विक गिरावट को बताया गया, न कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी के अवशोषण (absorption) को।
 - अवशोषण का निर्धारण एक्सपोर्टर-वार किया जाना चाहिए, और किसी अलग-अलग एक्सपोर्टर के खिलाफ अवशोषण साबित करने के लिए देश-व्यापी डेटा या भाग न लेने वाले एक्सपोर्टर के लेन-देन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
 - ड्यूटी लगने के बाद हुए कुल 51 MT इम्पोर्ट में से केवल 5 MT कम कीमत पर थे; इतने सीमित और इक्का-दुक्का इम्पोर्ट से यह साबित नहीं हो सकता कि ड्यूटी बेअसर हो गई थी।

- iv. 5 MT वाले लेन-देन को विशेष रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह प्रतिनिधि (representative) नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें भाग न लेने वाला एक्सपोर्टर शामिल था और यह MIP फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर था।
- v. झूटी लगने के बाद का केवल लगभग चार महीने का डेटा उपलब्ध था, जिसे अवशोषण का निर्धारण करने के लिए अपर्याप्त बताया गया।
- vi. MIP के कामकाज का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि वास्तविक मूल्य निर्धारण व्यवहार का आकलन करने के लिए MIP-अनुपालन वाले लेन-देन पर विचार किया जाना चाहिए, न कि MIP से कम कीमत वाले इक्का-दुक्का इम्पोर्ट पर।
- vii. इस दृष्टिकोण को DGTR की पिछली कार्यप्रणाली के असंगत बताया गया, जिसमें एक्सपोर्टर-विशिष्ट सबूत की आवश्यकता होती थी।
- viii. नियम 2(b), नियम 5(3A) (ii) की प्रयोज्यता और अवशोषण के निष्कर्ष के लिए एक्सपोर्टर-विशिष्ट सबूत की आवश्यकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया।
- ix. मूल निष्कर्षों पर चुनिंदा रूप से निर्भरता को चुनौती दी गई, विशेष रूप से कीमतों में वैश्विक गिरावट की कथित अनदेखी को।
- x. संभावित संबंध/इम्पोर्ट के आधार पर DI के रूप में UPL की नियम 2(b) पात्रता पर सवाल उठाया गया और सत्यापन का अनुरोध किया गया।
- xi. झूटी में प्रस्तावित संशोधन/पिछली तारीख से लागू करने (पिछली तारीख से लागू होना) को भी चुनौती दी गई।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जानकारी/टिप्पणियाँ

50. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं।

- i. मुख्य कच्चे माल की कीमतों में केवल 7.4% की गिरावट के मुकाबले एक्सपोर्ट की कीमत में 46% की गिरावट यह दर्शाती है कि एक्सपोर्ट की कीमत में कमी उत्पादन लागत में कमी के अनुपात में नहीं थी और इसलिए नियम 29(1) के तहत अवशोषण साबित होता है।
- ii. एक्सपोर्ट की कीमत में गिरावट USD और INR दोनों ही रूपों में स्पष्ट है; इसलिए, यह तर्क कि गिरावट रुपये की कीमत घटने के कारण हुई, सही नहीं है।
- iii. नियम 29(1) एब्जॉर्प्शन (लागत सोखने) के लिए तीन विकल्प देता है; इनमें से किसी एक शर्त का पूरा होना ही काफी है, तीनों शर्तों का एक साथ पूरा होना ज़रूरी नहीं है।
- iv. कीमतों में वैश्विक गिरावट का मतलब यह नहीं है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, क्योंकि मुख्य बात यह है कि क्या भारत को किए गए निर्यात की कीमत में कमी, उत्पादन लागत में बदलाव के अनुपात में थी; इस मामले में, निर्यात कीमत में गिरावट कच्चे माल की लागत में गिरावट से कहीं ज्यादा थी।
- v. आयात की कम मात्रा एब्जॉर्प्शन को नहीं रोकती; मुख्य बात कीमत तय करने का तरीका है और यह देखना है कि क्या इससे झूटी का सुधारात्मक असर कम हो रहा है। इसलिए, एमआईपी से कम कीमत वाले 5 मीट्रिक टन आयात भी महत्वपूर्ण हैं।
- vi. 5 मीट्रिक टन के लेन-देन को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि इसकी मात्रा कम थी; निर्यातक यह साबित करने के लिए सबूत नहीं दे पाया कि एमआईपी के नियमों के अनुसार तय की गई कीमतें उसके स्वतंत्र मूल्य निर्धारण का नतीजा थीं।

- vii. एमआईपी और एंटी-डंपिंग शुल्क अलग-अलग उपाय हैं। एमआईपी का पालन करने से वास्तविक निर्यात कीमतों की जांच नहीं रुकती, और एमआईपी एक प्रभावी एंटी-डंपिंग शुल्क की जगह नहीं ले सकता।
- viii. जनवरी-सितंबर 2025 की एब्जॉर्प्शन अवधि सही है, क्योंकि नियम 29 में ड्यूटी के बाद की न्यूनतम अवधि तय नहीं की गई है; इसके अलावा, जिन लेन-देन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया, वे 8 मई 2025 को एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने के बाद हुए थे।
- ix. कल्याणी स्टील्स और नियम 5(3A) (ii) पर निर्भरता को गलत बताया गया क्योंकि मौजूदा समीक्षा नियम 29 और 30 के तहत होती है और नियम 29 में शुरुआती जांच के लिए ज़रूरी 12 महीने की पीओआई (जांच की अवधि) की शर्त लागू नहीं होती है।
- x. निर्यात कीमत तय करने के लिए चीन के कस्टम्स डेटा पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह उस कीमत को दिखाता है जिस पर सामान निर्यात किया गया था, जबकि भारतीय CIF वैल्यू में एमआईपी के नियमों के अनुसार घोषित वैल्यू हो सकती है, न कि वास्तविक निर्यात कीमत।
- xi. जहां निर्यातक के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, वहां अथॉरिटी नियम 6(8) के तहत उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर भरोसा कर सकती है।
- xii. डंपिंग और नुकसान का मार्जिन बढ़कर 85-95% हो गया, जबकि लैंडेड कीमत में लगभग 45% की गिरावट आई, जबकि NIP में केवल 18% की गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि ड्यूटी बेअसर रही।
- xiii. डीआई की पात्रता से जुड़े नियम 2(b) के तहत आपत्ति के लिए कथित संबंधों/आयात की पुष्टि ज़रूरी है; हालाँकि, उपलब्ध सबमिशन में खास तौर पर ऐसी पुष्टि का अनुरोध किया गया है और यह अपने आप में अयोग्यता साबित नहीं करता है।
- xiv. ड्यूटी के प्रकार के संबंध में, उत्पाद के रूप, सांद्रता (एकाग्रता) और लेनदेन मूल्य में अंतर को ध्यान में रखते हुए 'एड-वैलोरम' (मूल्यानुसार) ड्यूटी का अनुरोध किया गया था।
- xv. यह बताया गया कि डाउनस्ट्रीम यूज़र्स पर एंटी-डंपिंग शुल्क का असर बहुत कम होगा, जिसका अनुमान लगभग ₹35-36 प्रति बोतल लगाया गया है।

च.3 अथॉरिटी द्वारा जांच

- 51. अथॉरिटी ने देखा है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू होने के बाद, भारत को भेजे जाने वाले संबंधित सामान की एक्सपोर्ट कीमत में लगभग 46% की गिरावट आई, जबकि उसी दौरान मुख्य कच्चे माल की कीमतों में केवल 7.4% की कमी आई। एक्सपोर्ट कीमत में इतनी बड़ी गिरावट को इनपुट लागत में बदलाव से नहीं समझाया जा सकता, और यह गिरावट अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये, किसी भी मुद्रा में मापे जाने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए, इसे केवल एक्सचेंज-रेट में उतार-चढ़ाव या वैश्विक कीमतों में बदलाव का नतीजा नहीं माना जा सकता; यह एक्सपोर्ट कीमत में ऐसी कमी को दर्शाता है जो प्रोडक्शन की लागत में हुए किसी भी संबंधित बदलाव के अनुपात में नहीं है।
- 52. अथॉरिटी इस बात को भी नहीं मान सकती कि एमआईपी से कम कीमत पर होने वाले इंपोर्ट की मात्रा इतनी कम है कि उससे 'एब्जॉर्प्शन' (लागत या शुल्क का अवशोषण) का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। नियम 29 के तहत जांच एक्सपोर्ट के कीमत तय करने के तरीके और ड्यूटी के लगातार असरदार बने रहने पर केंद्रित होती है; न तो नियम 29 और न ही एक्ट की धारा 9A(1B) ऐसे निष्कर्ष के लिए इंपोर्ट की किसी न्यूनतम मात्रा को शर्त के तौर पर तय करती है। अहम बात यह है कि क्या ड्यूटी लगने के बाद भारत को होने वाले एक्सपोर्ट की कीमत में ऐसी गिरावट आई है जिससे ड्यूटी का सुधारात्मक असर कम हो गया हो; जिस मात्रा पर यह गिरावट देखी गई है, उससे यह सवाल तय नहीं होता। इसके अलावा, कीमत तय करने का यह तरीका सिर्फ एमआईपी से कम कीमत वाले कंसाइनमेंट तक ही सीमित नहीं है। हिस्सा लेने वाले एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट को इंपोर्ट के समय MIP या उसके

आस-पास की कीमत पर इसलिए घोषित किया गया था क्योंकि उस कीमत का पालन करना ज़रूरी था; एक्सपोर्टर के अपने वेरिफाइड रिकॉर्ड — ERP डिलीवरी नोट से पुष्टि किए गए ग्रुप ट्रांसफर इनवॉइस — के अनुसार उनकी असल नेट एक्सपोर्ट कीमत 5.85 से 6.25 USD प्रति किलोग्राम के दायरे में थी, यानी यह कीमत उस कंसाइनमेंट के लगभग बराबर थी जो MIP की शर्त के बिना आया था। इस तरह, हिस्सा लेने वाले एक्सपोर्टर के अपने कंसाइनमेंट में भी असल एक्सपोर्ट कीमत में वैसी ही कमी दिखाई देती है, और यह तथ्य कि MIP से कम कीमत वाला कंसाइनमेंट ड्यूटी लगाने के बाद कुल इंपोर्ट की गई मात्रा का केवल 10% था, अपने आप में 'एब्जॉर्प्शन' के निष्कर्ष को नहीं रोकता है।

53. USD 5.5–6/kg पर 5 MT का इंपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कीमतें एमआईपी से कम हैं। एमआईपी के आसपास क्लियर किए गए बाकी इंपोर्ट को, बिना सबूत के, स्वतंत्र कमर्शियल प्राइसिंग का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब एक्सपोर्टर ने इसे साबित न किया हो।
54. एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) और एंटी-डंपिंग शुल्क अलग-अलग विधानों के अंतर्गत लागू होने वाले पृथक एवं स्वतंत्र उपाय हैं। एमआईपी के अनुरूप घोषित कीमतें नियामकीय अनुपालन को दर्शा सकती हैं और आवश्यक रूप से वास्तविक निर्यात कीमतों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। अतः प्रासंगिक चीन सीमा शुल्क डेटा तथा सहायक चालानों सहित वास्तविक निर्यात कीमतों पर विचार किया गया है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि घोषित आयात मूल्य केवल एमआईपी के लागू होने के कारण न्यूनतम आयात मूल्य के आसपास रहे, जबकि वास्तविक निर्यात कीमतें काफी कम थीं। यदि एमआईपी लागू नहीं होता, तो संबंधित वस्तुओं के इन काफी कम मूल्यों पर आयातित होने की पूरी संभावना थी, जिसके परिणामस्वरूप गैर-हानिकारक मूल्य से काफी कम लैंडेड मूल्यों पर आयात में वृद्धि होती। इस प्रकार, वर्तमान में एमआईपी ने सीमा पर वास्तविक निर्यात कीमतों में हुई कमी को छिपाया है; इसने एंटी-डंपिंग शुल्क के अवशोषण को समाप्त नहीं किया है। यह निष्कर्ष इस बात को और पुष्ट करता है कि लागू शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव कमजोर हुआ है।
55. जहां मौका मिलने के बावजूद ट्रांज़ैक्शन-वार/तीसरे देश की पूरी जानकारी नहीं दी गई है, वहां अथॉरिटी नियम 6(8) के तहत उपलब्ध सबसे अच्छी जानकारी पर भरोसा कर सकती है।
56. अथॉरिटी ने देखा कि नियम 29 में ड्यूटी के बाद की कोई न्यूनतम अवधि तय नहीं की गई है। एब्जॉर्प्शन के निष्कर्ष का आधार बनने वाले संबंधित ट्रांज़ैक्शन 8 मई 2025 के बाद हुए थे; इसलिए, पहले की अवधि को शामिल करने से जांच अमान्य नहीं हो जाती।
57. नियम 5(3A) (ii) नियम 5 के तहत मूल जांच पर लागू होने वाली POI (जांच की अवधि) की आवश्यकता से संबंधित है और इसे नियम 29 और 30 के तहत की जा रही मौजूदा समीक्षा पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।
58. अथॉरिटी ने एक्सपोर्टर-वार जांच और डीजीटीआर की पिछली प्रैक्टिस के बारे में दी गई जानकारी पर विचार किया है। यह फैसला मौजूदा जांच में उपलब्ध सबूतों पर आधारित है, जिसमें रिकॉर्ड पर मौजूद प्राइसिंग की जानकारी भी शामिल है; जहां लागू हो, वहां एक्सपोर्टर-विशिष्ट पूरी जानकारी न होने पर नियम 6(8) के तहत कार्रवाई की जाती है।
59. अथॉरिटी ने डी आई की स्थिति/संभावित संबंधित-पार्टी आयात के संबंध में नियम 2(b) के तहत उठाई गई आपत्ति पर भी विचार किया है। आवेदकों का यूई में एक संबंधित आयातक है, जो एक गैर-विषय देश है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि यूई में उस इकाई द्वारा खरीदा गया उत्पाद बाद में भारत को निर्यात किया गया हो। इसलिए, अथॉरिटी का मानना है कि नियम 2(b) के संबंध में आवेदक की पात्रता को लेकर कोई लंबित मुद्दा नहीं है।
60. पुनर्मूल्यांकन करने पर, डंपिंग और नुकसान (इंजरी) मार्जिन बढ़कर 85–95% हो गए, जबकि एनआईपी में लगभग 18% की गिरावट के मुकाबले लैंडेड कीमत में लगभग 45% की गिरावट आई; इससे यह साबित होता है कि ड्यूटी के बाद भी लैंडेड कीमत एनआईपी से काफी नीचे बनी रही।

61. इसके अनुसार, अथॉरिटी का मानना है कि निर्यात कीमत में गिरावट, उत्पादन लागत में आई गिरावट के अनुपात में नहीं थी और मौजूदा एंटी-डंपिंग ड्यूटी, नियम 29 के अर्थ में अप्रभावी हो गई है। नतीजतन, नियम 29(2) के तहत ड्यूटी के स्वरूप/मात्रा में उचित बदलाव की जांच की गई है।

छ. निष्कर्ष

62. सभी संबंधित पक्षों की दलीलों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने; और रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर विचार करने के बाद, अथॉरिटी इस नतीजे पर पहुंची है:
1. मौजूदा एंटी-एब्जॉर्प्शन जांच शुरू करने के लिए आवेदन, नियमों के नियम 30 के अनुसार भारत में समान उत्पाद के उत्पादकों के तौर पर आवेदकों द्वारा दायर किया गया था, और जांच 2 मार्च 2026 की अधिसूचना संख्या 7/02/2026-DGTR के तहत शुरू की गई थी।
 2. विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में था, यानी ग्लुफोसिनेट और इसके साल्ट (लवण), तकनीकी और फॉर्मूलेशन दोनों रूपों में; घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबंधित सामान समान उत्पाद हैं; और स्टैंडिंग, नुकसान और कारण संबंध के बारे में मूल जांच के निष्कर्षों को फिर से नहीं खोला जा रहा है।
 3. डीजी सिस्टम्स का ट्रांज़ैक्शन-वार डेटा एब्जॉर्प्शन अवधि के दौरान संबंधित सामान के 66 मीट्रिक टन के आयात को रिकॉर्ड करता है, जिसमें से 51 मीट्रिक टन का आयात 8 मई 2025 को एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू होने के बाद किया गया था। ड्यूटी लागू होने के बाद की मात्रा में से, 5 मीट्रिक टन न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) के दायरे से बाहर के टैरिफ आइटम के तहत 5.91 USD प्रति किलोग्राम के सीआईएफ मूल्य पर आए, और बाकी न्यूनतम आयात मूल्य के दायरे में आए।
 4. जो खेप न्यूनतम आयात मूल्य की बाध्यता से मुक्त होकर आई, उसकी कीमत आवेदकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए चीन कस्टम्स के निर्यात डेटा में दिख रही एफओबी निर्यात कीमतों से काफी हद तक मेल खाती है, और इसे भारत को संबंधित सामान के वास्तविक निर्यात मूल्य के प्रतिनिधि के रूप में अपनाया गया है।
 5. इस आधार पर, एब्जॉर्प्शन अवधि के दौरान शुद्ध निर्यात मूल्य 5.561 USD प्रति किलोग्राम है, जबकि मूल जांच में यह 10.259 USD प्रति किलोग्राम तय किया गया था; यानी इसमें लगभग 46% की गिरावट आई है।
 6. भाग लेने वाले निर्यातकों ने न तो मार्केट इकोनॉमी ट्रीटमेंट का दावा किया है और न ही मार्केट इकोनॉमी प्रश्नावली भरी है, और इसलिए उनका लागत डेटा सत्यापन योग्य रूप में उपलब्ध नहीं है; उत्पादन लागत में बदलाव की जांच मुख्य कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर एक सरोगेट (विकल्प) के रूप में की गई है, जिसमें लगभग 7.4% की गिरावट दिखाई देती है।
 7. इसलिए, भारत को होने वाले निर्यात की कीमत में आई कमी, उत्पादन लागत में हुए बदलाव के अनुपात में नहीं है, और नियम 29(1) के पहले हिस्से के तहत 'एब्जॉर्प्शन' (लागत या शुल्क का अवशोषण) की शर्त पूरी होती है।
 8. भाग लेने वाले निर्यातकों ने किसी भी ट्रांज़ैक्शन के लिए तीसरे देश को किए गए निर्यात का डेटा रिकॉर्ड पर नहीं रखा है, और रिकॉर्ड पर मौजूद रीसेल-प्राइस (पुनर्विक्रय मूल्य) का डेटा स्वतंत्र रूप से 'एब्जॉर्प्शन' का संकेत नहीं देता है; नियम 29(1) के अलग-अलग हिस्सों को देखते हुए, यह निष्कर्ष पहले हिस्से पर आधारित है।

9. नियम 29(2) के तहत दोबारा मूल्यांकन करने पर, 'एब्जॉर्प्शन' की अवधि के लिए 'कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल वैल्यू' (तय की गई सामान्य कीमत) 10.565 USD प्रति किलोग्राम और 'नॉन-इंजुरियस प्राइस' (बिना नुकसान वाली कीमत) 12.415 USD प्रति किलोग्राम है।
10. डंपिंग मार्जिन मूल अवधि में 20-30% की रेंज से बढ़कर 'एब्जॉर्प्शन' अवधि में 85-95% की रेंज में पहुंच गया है, और इंजरी मार्जिन (नुकसान का मार्जिन) भी 20-30% की रेंज से बढ़कर 85-95% की रेंज में पहुंच गया है। मूल अवधि के लिए तय किया गया डंपिंग मार्जिन, जो 2.998 USD प्रति किलोग्राम था, वर्तमान में लागू एंटी-डंपिंग ड्यूटी के अनुरूप है। प्रति-यूनिट के हिसाब से, दोबारा तय किया गया डंपिंग मार्जिन (जो *** है) दोनों मार्जिन में से कम वाला है।
11. वर्तमान में लागू एंटी-डंपिंग ड्यूटी को ध्यान में रखने के बाद भी, संबंधित आयात की 'लैंडेड प्राइस' (आयातित माल की भारत में पहुंचने पर कीमत) 'नॉन-इंजुरियस प्राइस' से काफी कम बनी हुई है।
12. इसके अनुसार, वर्तमान में लागू एंटी-डंपिंग ड्यूटी को निर्यातकों द्वारा 'एब्जॉर्ब' (अवशोषित) कर लिया गया है और यह एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 29 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 9A(1B) के अर्थ में अप्रभावी हो गई है।
13. एंटी-डंपिंग ड्यूटी की बदली हुई मात्रा केवल भविष्य के लिए लागू होगी, न कि पिछली तारीख से (बिना रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के); जबकि ड्यूटी का मौजूदा स्वरूप वैसा ही रहेगा और केवल उसकी मात्रा में बदलाव किया जाएगा।

झ. सिफारिश

63. अथॉरिटी ने देखा कि जांच शुरू की गई और सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना दी गई। साथ ही, घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य संबंधित पक्षों को 'एब्जॉर्प्शन' (लागत या शुल्क का बोझ खुद उठाना) के पहलू पर सकारात्मक जानकारी देने का पूरा मौका दिया गया। एंटी-डंपिंग नियमों के तहत चीनी उत्पादकों पर शुल्क के एब्जॉर्प्शन की जांच शुरू करने और उसे पूरा करने के बाद, अथॉरिटी का मानना है कि चीनी उत्पादकों पर लागू एंटी-डंपिंग शुल्क में बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए, अथॉरिटी संबंधित देश से संबंधित सामान के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा में बदलाव की सिफारिश करती है।
64. अथॉरिटी, चीन (PR) से आने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले संबंधित सामान पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा में बदलाव की सिफारिश करती है। यह बदलाव 'फाइनल फ़ाईंडिंग नोटिफिकेशन' नंबर F. No. 6/19/2024- डीजीटीआर (10 फ़रवरी 2025) और नोटिफिकेशन नंबर 09/2025-कस्टम्स (एंटी-डंपिंग शुल्क) (8 मई 2025) के तहत नीचे दिए गए तरीके से किया जाएगा। मामले के तथ्यों, दी गई जानकारी और संबंधित पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा में बदलाव करना उचित समझा गया है। एंटी-डंपिंग शुल्क की बदली हुई मात्रा केवल भविष्य के लिए लागू होगी और इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा; साथ ही, एंटी-डंपिंग शुल्क का मौजूदा रूप/प्रकार वही रहेगा, केवल उसकी मात्रा में बदलाव किया जाएगा।
65. अथॉरिटी ने घरेलू इंडस्ट्री की उस रिक्वेस्ट पर विचार किया है जिसमें नियम 31 के तहत जांच शुरू होने की तारीख से बदले हुए ड्यूटी को पिछली तारीख से लागू करने और जांच शुरू होने के समय नियम 30(5) के तहत प्रोविज़नल असेसमेंट की सिफारिश की गई थी। नियम 31 पिछली तारीख से लागू करने की इजाज़त देता है, लेकिन इसके लिए मजबूर नहीं करता; यह मामला अथॉरिटी के विवेक पर निर्भर करता है, जिसमें रिव्यू के सुधारात्मक मकसद और 'कम-ड्यूटी' के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। यह मकसद सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं, और ड्यूटी में भविष्य के लिए बदलाव करके इसे पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है। रिव्यू के दौरान, संबंधित सामान भारत में घोषित मूल्यों पर आया, जो न्यूनतम आयात मूल्य के बराबर या उसके आसपास थे - यानी, गैर-हानिकारक मूल्य के बराबर या उससे अधिक - और उन पर उस समय लागू ड्यूटी लगाई गई थी; भारत में उनकी रीसेल कीमत में कोई

गिरावट नहीं देखी गई; इसलिए, पिछली तारीख से ड्यूटी लगाकर रोकने के लिए हानिकारक लैंडेड मूल्यों पर आयात की कोई बाढ़ नहीं आई थी। यह 'एब्जॉर्प्शन' (लागत या ड्यूटी का बोझ खुद उठा लेने) के निष्कर्ष से अलग है, जो एक्सपोर्टर्स के वास्तविक एक्सपोर्ट-प्राइसिंग व्यवहार पर आधारित होता है और भविष्य के लिए ड्यूटी को फिर से तय करने की मांग करता है। 'कम-ड्यूटी' सिद्धांत को लागू करते हुए, अथॉरिटी भविष्य के लिए इसे लागू करना पर्याप्त मानती है और पिछली तारीख से लागू करने की सिफारिश नहीं करती है; इसलिए, नियम 30(5) के तहत प्रोविज़नल असेसमेंट वाले आयात का अंतिम असेसमेंट संबंधित अवधि के दौरान लागू ड्यूटी की दर पर किया जाएगा।

66. 'लेसर ड्यूटी रूल' (कम शुल्क का नियम) को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी घरेलू इंडस्ट्री को हुए नुकसान को दूर करने के लिए डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन (नुकसान के मार्जिन) में से जो भी कम हो, उसके बराबर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश करती है। इसके अनुसार, अथॉरिटी संबंधित देश से आने वाले या वहां से एक्सपोर्ट किए जाने वाले संबंधित सामान पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी की मात्रा में बदलाव करके उसे नीचे दी गई ड्यूटी टेबल के कॉलम 7 में बताई गई राशि के बराबर करने की सिफारिश करती है। बदली हुई ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन की तारीख से लागू होगी और 8 मई 2025 के नोटिफिकेशन नंबर 09/2025-कस्टम्स (एंटी-डंपिंग ड्यूटी) के तहत लगाई गई एंटी-डंपिंग ड्यूटी की बची हुई अवधि के लिए लागू रहेगी।

ड्यूटी टेबल

क्रम संख्या	हेडिंग/सब-हेडिंग*	सामान का विवरण	उत्पत्ति का देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	मात्रा	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 और 38089999	ग्लूफोसिनेट और उसका सॉल्ट	चीन पी आर	चीन पीआर (PR) सहित कोई भी अन्य देश	अन्य	5004	एम टी	यू एस डी
2	-do-	-do-	चीन पीआर (PR) सहित कोई भी अन्य देश	चीन पी आर	अन्य	5004	एम टी	यू एस डी

*कस्टम्स वर्गीकरण केवल संकेत देने वाला है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ज. आगे की प्रक्रिया

67. अंतिम निष्कर्षों के आधार पर अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ अपील, एक्ट के संबंधित प्रावधानों के अनुसार कस्टम्स, एक्साइज़ और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष की जा सकती है।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 1st September, 2026

Case No. AD (AA) – 01/2026

Subject: Anti-absorption investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of ‘Glufosinate and its salts’ originating in or exported from China PR.

F. No. 7/02/2026-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) thereof.

BACKGROUND OF THE INVESTIGATION

1. In accordance with the provisions of Rule 30 of the Anti-Dumping Rules, Superform Chemistries Limited, UPL Limited, Astral Life India Limited, United Phosphorus (India) LLP, UPL Sustainable Agri Solutions Limited and SWAL Corporation Limited (hereinafter referred to as the “applicants” or the “domestic industry”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) alleging absorption of anti-dumping duty imposed on imports of ‘Glufosinate and its salts’ (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The anti-dumping investigation concerning imports of Glufosinate and its salts from China PR was initiated vide notification No. 6/19/2024-DGTR dated 29th June 2024. Vide final finding F. No. 6/19/2024-DGTR dated 10th February 2025, the Authority recommended the imposition of anti-dumping duty on imports of Glufosinate and its salts from China PR for a period of 5 years. Such duties were levied by the Ministry of Finance vide Notification No. 09/2025-Customs (ADD) dated 8th May 2025. The table below sets out the duty in force at present:

Sl. No.	HS code	Producer	Amount
1	38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 and 38089999	Any producer	2,998 \$/MT

3. In terms of Section 9A(1B) of the Act and Rule 29(2) of the Rules, where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of existing anti-dumping duty, which is thereby rendered or may be rendered ineffective, the Designated Authority may, after conducting a review,

recommend modification in the form or basis of the duty and/or the quantum of anti-dumping duty after reassessing the dumping margin and injury margin. In accordance with the same, the Authority is required to review, based on an application with sufficient evidence, made by or on behalf of the domestic industry or any other interested party as to whether the existing anti-dumping duty is thereby rendered or may be rendered ineffective because of absorption of duty.

4. On the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, the Authority issued a public notice vide notification No. 7/02/2026-DGTR dated 2nd March 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 30 of the Rules, to determine the existence and effect of absorption of the anti-dumping duty on exports of the product under consideration from China PR and to recommend modification of the quantum or form of the anti-dumping duty.

A. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

a. Initiation

- i. The Authority vide notification No. 7/02/2026-DGTR dated 2nd March 2026 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-absorption investigation against imports of the subject goods from the subject country.
- ii. In accordance with Rule 30(4), prior to initiation of the investigation, the government of the subject country was notified through their embassy in India about the receipt of the present anti-absorption application.
- iii. In accordance with Rule 6(2), the interested parties were informed of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

b. Period of investigation (POI)

- i. As noted in the initiation notification, the period of absorption was considered as January 2025 to September 2025 (9 months). The Authority has compared the prices in such period to the prices in the period of investigation of the original investigation, i.e. 1st January 2023 to 31st December 2023 (“original POI”).

c. Import data

- i. A request was made to the DG Systems to obtain transaction-wise import data of the subject goods for the absorption period. The data was received

and has been relied upon for the necessary analysis after due examination of the transactions. The volume and value of imports have been considered based on the DG Systems transaction-wise data.

d. Circulation of non-confidential version of the application

- i. In accordance with Rule 6(3), a copy of the non-confidential version of the application was provided to the government of the subject country through their embassy in India, to the known exporters of the subject goods from the subject country, to the known importers/users in India and to other interested parties who requested a copy of the application in writing.

e. Participation by exporters of the subject country

- i. In accordance with Rule 6(4), exporter's questionnaires were sent to the following known producers/exporters to seek information regarding the normal value and net export price: Lier Chemical Co. Ltd.; Agrodragon Co. Ltd.; BASF; Shandong Binnong Technology Co. Ltd.; Limen Chemical Company Limited; Fuhua Tongda Agro-chemical Technology Co. Ltd.; Yongnong Biosciences Co. Ltd.; Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co. Ltd.; Shanghai Qizhou Ziyui Co. Ltd.; and Weifang Xinlu Chemical Co. Ltd.
- ii. The exporter's questionnaires were also sent to the government of the subject country through its embassy in India, with a request to forward the same to the producers/exporters of the subject goods and advise them to respond within the prescribed time limit.
- iii. In response, the following producers/exporters from the subject country filed exporter's questionnaire responses: (1) Xiangshui Zhongshan Bioscience Co. Ltd.; and (2) Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co. Ltd. The two companies are related, the former being the producer and the latter the exporter, and are hereinafter referred to together as the "participating exporters".

f. Participation by importers/users and their associations

- i. In accordance with Rule 6(4), questionnaires were also sent to the following known importers/users of the product under consideration in India: Crystal Crop Protection Private Limited; Krishi Rasayan; BASF India; and Amish Crop Science Private Limited.
- ii. In response, the following importers/users filed importer/user questionnaire responses: (1) Zhongshan Crop Science India Pvt. Ltd.; and (2) Tephra Bioscience LLP.

g. Registered interested parties

- i. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were

directed to circulate the non-confidential version of all their submissions to all other interested parties.

h. Oral hearing

- i. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 20th May 2026. The parties presenting their views were directed to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.

i. Further procedure

- i. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperative.
- ii. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative, and the findings have been recorded on the basis of the facts available.
- iii. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version thereof.
- iv. The non-injurious price has been determined based on the optimum cost of production and cost to make and sell the domestic like article in India, having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the principles laid down in Annexure III of the Rules, as re-assessed in accordance with Rule 29(2).
- v. All the arguments raised and information provided by all the interested parties, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered.
- vi. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final finding was issued to the interested parties on 20th August 2026 and the interested parties were allowed time up to 26th August 2026 to comment on the same. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and the comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the

extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence in this final finding notification.

- vii. “****” in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.
- viii. The exchange rate adopted for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 87.26. The exchange rate considered in the original investigation was 1 US\$ = Rs. 83.52.

B. SUBMISSIONS MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES ON VARIOUS ISSUES

6. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation:
- i. The respondents submitted that although they registered as interested parties on 8th April 2026, their registration was confirmed only on 15th April 2026. Accordingly, the non-confidential version of the application was effectively made available only on 15th April 2026. Consequently, the due date for filing questionnaire responses ought to have been 22nd May 2026 instead of 16th May 2026, and extension of time till 7th June 2026, along with condonation of delay, was sought.
 - ii. The initiation of the present anti-absorption investigation is unsustainable as the applicants failed to establish a prima facie case under Rules 29 and 30. The application is based on incomplete and insufficient evidence and relies primarily on the alleged decline in export prices without examining other relevant factors, including changes in production costs in China PR, resale prices in India, market conditions and third-country export prices.
 - iii. A mere decline in export prices does not establish absorption. Rule 29 requires examination of whether the decline is attributable to absorption of anti-dumping duties and not to other factors such as reduction in production costs. In the present case, there has been no demonstrated decline in production costs in China PR, nor have the applicants furnished data relating to resale prices in India or the cost of production in China PR. Reliance on the domestic industry's raw material costs is contrary to Rule 29.
 - iv. The applicants have failed to disclose the source and basis of the export price data, import volume data and cost information relied upon in the application. The export price data does not cover the entire absorption period and the alleged changes in production costs are unsupported by evidence.
 - v. The third-country export price evidence relied upon by the applicants consists only of selective invoices relating to two Chinese exporters and is unsupported by evidence of actual exports, deliveries or payments. Such invoices have not been authenticated by the concerned exporters and therefore cannot form the basis of an anti-absorption investigation.

- vi. The alleged decline in export prices to India is consistent with the decline in export prices to third countries and therefore does not establish absorption. Further, once the applicable anti-dumping duty and the Minimum Import Price (MIP) are considered, export prices to India have in fact increased as compared to the original period of investigation.
- vii. The domestic industry has continued to enjoy MIP protection throughout the absorption period, which has subsequently been extended. Of the alleged 71 MT imports during the absorption period, nearly 56 MT (approximately 80%) were imported at prices exceeding USD 15/kg, demonstrating that the overwhelming majority of imports cannot be regarded as absorbed imports.
- viii. Rule 29 applies only after the imposition of anti-dumping duties. Therefore, the Authority lacks jurisdiction to examine imports made prior to 8th May 2025. The proposed nine-month POI improperly includes the pre-duty period, leaving only four months of post-duty data, which is insufficient for any meaningful anti-absorption analysis.
- ix. Although Rule 29 does not prescribe a specific POI, the Authority's discretion is not unfettered. The determination of the POI should be guided by Rule 5(3A)(ii), which contemplates a normal twelve-month POI and requires recorded reasons for any deviation, as recognised in *Kalyani Steels Ltd. v. Union of India*.
- x. The applicants themselves proposed the nine-month POI, which was accepted by the Authority. However, there is no legal basis under Rule 29 for comparing the present investigation period with the original period of investigation, and taxing statutes must be construed strictly without reading into the Rule requirements that do not exist.
- xi. The applicants have failed to establish that the existing anti-dumping duty has become ineffective. According to the applicants' own data, only about 56 MT of imports entered India after imposition of anti-dumping duties, of which only about 10 MT were allegedly imported at lower prices. Such insignificant quantities cannot establish duty absorption under Rule 29.
- xii. The request for modification of the form of anti-dumping duty is unsupported by Rule 29(2). The applicants have neither justified why modification is warranted nor specified the modified form of duty sought. Any modification must be based upon the Authority's independent objective analysis and cannot be founded upon the applicants' apprehension regarding the expiry of the MIP, since MIP and anti-dumping duties are distinct and mutually exclusive trade remedial measures.
- xiii. The scope of an anti-absorption review is confined to restoring the effectiveness of an existing anti-dumping duty. It does not permit reconsideration of the form or structure of the duty, which may only be undertaken in an appropriate mid-term or sunset review.

- xiv. The applicants have failed to justify retrospective modification of the anti-dumping duty.
- xv. Any imports below the notified MIP indicate deficiencies in customs or DGFT enforcement rather than absorption of anti-dumping duties. Enforcement of MIP falls within the jurisdiction of the Customs authorities and the DGFT and cannot be addressed through anti-absorption proceedings.
- xvi. The applicants have violated Rule 7 by claiming excessive confidentiality over export prices to India and third countries, purchase details, landed price calculations, net export price, normal value, dumping margin, injury margin, and the non-injurious price determined in the original investigation, thereby preventing meaningful defence by the interested parties.
- xvii. UPL is not eligible to constitute the domestic industry. The applicants relied upon invoices involving UPL entities located in Hong Kong and the UAE without disclosing their relationship with the applicants. The applicants may themselves be related to exporters or importers of the subject goods.
- xviii. The request for provisional assessment and guarantees from importers is unwarranted, as it would disrupt legitimate trade, increase compliance burdens and adversely affect the market despite the application itself being based on insufficient evidence.
- xix. Anti-absorption proceedings are exporter-specific and require an objective assessment of the conduct of each exporter. Exporters that have not reduced their export prices after imposition of anti-dumping duties, or which did not export during the relevant period, cannot lawfully be subjected to enhanced anti-absorption duties merely because other exporters are alleged to have absorbed the duty.
- xx. Any enhancement or extension of anti-dumping duties would adversely affect downstream industries and users dependent on the subject goods by increasing input costs, reducing competitiveness in domestic and export markets, and ultimately increasing costs for end consumers, particularly farmers.

C. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY ON VARIOUS ISSUES

- 7. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation:
 - i. The product under consideration is Glufosinate and its salts, in both technical and formulation forms. Although the Customs Tariff classifications and HS Codes have undergone changes over time, the scope of the product under consideration has remained unchanged.
 - ii. Imports of the product under consideration have remained subject to both anti-dumping duties and MIP measures. The successive MIP notifications, culminating in the notification dated 13th April 2026, align the scope of the MIP with that of the

- anti-dumping duty and expressly factor in the anti-dumping duty, demonstrating that the existing anti-dumping duty alone has not been sufficient to prevent imports at injurious prices.
- iii. The interested parties failed to comply with the procedural requirements prescribed by the Authority by not filing confidentiality comments and questionnaire responses within the stipulated time. Requests for extension were made belatedly after the domestic industry pointed out the default and therefore cannot cure the procedural non-compliance.
 - iv. The Authority's internal timeline for completion of the investigation does not confer any right upon the interested parties to seek extensions beyond the prescribed timelines.
 - v. The Economic Interest Questionnaire is irrelevant in an anti-absorption investigation. Proceedings under Rule 29 are confined to examining whether exporters have absorbed the anti-dumping duty and do not reopen issues relating to dumping, injury, causal link, domestic industry or public interest already determined in the original investigation.
 - vi. Continuation and effective enforcement of anti-dumping duties is not against public interest. The domestic industry has adequate capacity to meet domestic demand, has made significant investments, generated employment and contributes to environmental sustainability. Further, the anti-dumping duty would increase the cost of a bottle of formulation by only about Rs. 35-36, sufficient for one acre of cultivation, resulting in negligible impact on farmers.
 - vii. Rule 29 requires the Authority to examine whether exporters have reduced export prices without a corresponding reduction in production costs, thereby rendering the existing anti-dumping duty ineffective. Rule 29(2) permits only adjustment of the previously determined normal value and injury parameters and does not require a fresh determination of normal value, injury or China's non-market economy status.
 - viii. The export price determined in the original investigation was USD ***/kg, whereas the average FOB export price during the anti-absorption period declined to USD ***/kg, representing a decline of about 44% despite the imposition of anti-dumping duties.
 - ix. The applicants relied upon actual export prices obtained from China Customs export data. Since imports into India were subject to the MIP, Indian Customs import prices were artificially influenced by MIP compliance and therefore do not represent the exporters' actual pricing behaviour. Transaction-wise export data consistently shows prices around USD 5.78-5.79/kg.
 - x. The decline in export prices is not explained by any commensurate reduction in production costs. While raw material costs declined by only about Rs. 100/kg, export prices declined by approximately Rs. 335/kg. The participating exporters

neither claimed market economy treatment nor established any corresponding decline in production costs.

- xi. The contention that Rule 29 is not satisfied because export prices to third countries also declined is misconceived. Section 9A(1B) and Rule 29 use the word “or”, making each condition independent. Once export prices decline without a commensurate reduction in production costs, absorption is established.
- xii. The applicants relied upon the best information reasonably available, including China Customs data, transaction-wise export prices, internationally published raw material prices, third-country export data and purchase invoices. Domestic producers cannot reasonably be expected to possess exporters’ internal cost records or resale prices in India.
- xiii. The applicants have not relied solely upon raw material costs. Their claim is based on export prices, import volumes, production costs and other corroborative evidence covering the entire anti-absorption period.
- xiv. The participating exporters themselves failed to place evidence demonstrating any reduction in their production costs corresponding to the decline in export prices. Consequently, adverse inference may be drawn against them.
- xv. Rule 29(2) expressly empowers the Authority to modify the form, basis and quantum of anti-dumping duty. Since both dumping and injury margins have increased and the landed price continues to remain below the adjusted non-injurious price, modification of the existing measure is warranted.
- xvi. The request for modification is founded solely on the evidence of duty absorption and not on the existence or expiry of the MIP. The subsequent continuation of the MIP, while expressly accounting for the anti-dumping duty, further demonstrates that the existing anti-dumping duty has not achieved its intended remedial effect.
- xvii. During the original investigation the domestic industry had itself requested benchmark-form duties because of the existence of the MIP. The subsequent regulatory developments reinforce the need for modification of both the form and quantum of duty.
- xviii. The objections regarding confidentiality are belated. In any event, confidential treatment has been claimed only for business-sensitive information. Meaningful non-confidential summaries and indexed calculations were provided in accordance with Trade Notice No. 10/2018, and the interested parties have failed to identify any actual prejudice caused to them.
- xix. UPL continues to qualify as a domestic producer. The transactions relied upon by the interested parties relate to purchases made by overseas related entities and not imports into India by UPL. In any event, standing was conclusively determined in the original investigation and cannot be reopened.

- xx. Rule 31 expressly authorises retrospective application of any modified anti-dumping duty from the date of initiation once absorption is established.
- xxi. Rule 29(3) does not prescribe the period of investigation. Accordingly, the anti-absorption period selected by the Authority, consisting of post-duty transactions, is consistent with the Rules.
- xxii. Comparison of export prices prevailing during the anti-absorption period with those determined in the original investigation is inherent in Rule 29 and is consistent with the Authority's previous anti-absorption investigations as well as the practice followed by the European Commission.
- xxiii. The quantity of imports is not determinative in an anti-absorption investigation. Even limited import volumes may demonstrate that exporters have absorbed the anti-dumping duty and indicate the likelihood of future injurious imports.
- xxiv. In view of the substantial decline in export prices without any commensurate reduction in production costs, the existing anti-dumping duty has been absorbed by the Chinese exporters and no longer provides the intended remedial effect. The Authority should therefore modify the form, basis and quantum of the anti-dumping duty in terms of Rule 29(2).

D. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

8. As the present investigation is an anti-absorption review of the anti-dumping duty in force, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The scope of the product under consideration concluded by the Authority in the original investigation vide Final Finding F. No. 6/19/2024-DGTR dated 10th February 2025, and attracting the anti-dumping duty, is as below:

“18. In view of the above, the Authority concludes that the scope of product under consideration in the present investigation is Glufosinate and its salts, both in technical and formulation form.”

9. Glufosinate is a herbicide known for its effectiveness in controlling a broad spectrum of weeds. Its active ingredient disrupts the plant's ability to produce certain essential amino acids, leading to inhibition of protein synthesis and subsequent plant death. It is a phosphinic acid belonging to the organophosphorus chemical family, distinct from any other chemical class of herbicides.
10. The product under consideration does not have a dedicated classification. For the purpose of the present investigation, the codes 38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 and 38089999 have been considered. The customs classification code is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.
11. The Authority notes that the present investigation is an anti-absorption investigation, and the purpose is to examine whether the export price has moved in line with the cost of production. None of the interested parties has made any submission on the scope of the

product under consideration, nor has any interested party claimed that there is a difference in the product exported in the original investigation and the present investigation. Accordingly, the subject goods produced by the domestic industry are treated as “like article” to the product imported from China PR, and the Authority does not find it necessary to examine the issue of scope of product under consideration or like-article any further.

Miscellaneous issues, timeliness, standing and confidentiality

12. The non-confidential version of the information provided by various interested parties was made available to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018. Rule 7 of the Rules provides as follows:

“(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6 ... the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof ... (3) ... if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted ... it may disregard such information.”

13. The Authority has examined the submissions of the domestic industry and the other interested parties on confidentiality. The initiation notification provided an opportunity to all interested parties to offer comments on the confidentiality claims within the prescribed period of seven days from circulation of the non-confidential documents. No comments on confidentiality were received from the other interested parties within the stipulated time, and the objections were raised for the first time in the written submissions filed after the oral hearing. The Authority notes that confidentiality has been claimed in respect of information such as normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, sales and purchase documents, and names of customers and suppliers, all of which constitute business-sensitive information. In accordance with Rule 7 and the consistent practice of the Authority, and having regard to Trade Notice No. 10/2018, sensitive parameters such as the weighted-average normal value, non-injurious price, dumping margin and injury margin have been disclosed in the form of ranges. The Authority is satisfied that the confidentiality claims are warranted and that the non-confidential versions on record provide sufficient information to enable the interested parties to reasonably understand the substance of the information submitted. The contention of abuse of confidentiality is, accordingly, not accepted.
14. The interested parties contended that the questionnaire responses were due at a later date and sought extension of time and condonation of delay. The Authority considered and accepted the request for extension. Accordingly, the submissions filed pursuant to the

extension have been considered on merit, to the extent relevant. As the participating producers/exporters neither claimed market economy treatment nor filed the market economy questionnaire, verifiable cost and price data are unavailable. Accordingly, the normal value has been determined as per the methodology adopted in the original investigation, as discussed in Section E3.

15. The other interested parties have contended that the application does not make out a prima facie case, that the evidence is inadequate under Rule 30(2), and that the initiation is therefore unsustainable. The Authority notes that Rule 30(2) requires the application to contain sufficient evidence as regards the existence of the circumstances referred to in Rule 29(1) to justify initiation. The application contained transaction-level import data of the subject goods, evidence of the decline in export prices as compared with the original investigation, third-party data on raw-material prices and third-country export prices, and the reassessed dumping and injury margins. The Authority, having satisfied itself as to the sufficiency and adequacy of the prima facie evidence, recorded its reasons in the initiation notification dated 2nd March 2026. The adequacy of evidence for initiation is to be judged on the material available at the stage of initiation and not by the standard applicable to a final determination. The Authority is satisfied that the evidence was sufficient to justify initiation, and the contention is not accepted.
16. The other interested parties have contended that UPL is not eligible to be treated as domestic industry, being related to exporters or itself an importer of the PUC. The Authority notes that the standing of the domestic industry and its eligibility under Rule 2(b) were examined and determined in the original investigation. An anti-absorption investigation under Rule 29 is limited in scope to examining whether the exporters have absorbed the anti-dumping duty in force, and does not re-open issues such as standing, like-article, injury and causal link that were determined in the original investigation. In any event, the domestic industry has stated that UPL has not imported the product under consideration from China PR, and that the purchases relied upon by the interested parties were affected by related entities located outside India. The Authority does not find it necessary to re-examine the standing of the domestic industry in the present proceedings, and the contention is not accepted. The Authority equally notes the submission of the domestic industry concerning the commercial character of one of the responding importers and the nature of its activities. The determination in the present proceeding turns upon the export pricing behaviour of the exporters of the subject country and not upon the commercial character of the importers of record, and the Authority accordingly does not find it necessary to examine that submission.
17. The other interested parties have contended that the modification of the form of duty and any retrospective application would exceed the scope of anti-absorption proceedings, that the relief sought is punitive and exporter-agnostic, and that the enhancement would prejudice the user industry and farmers. The Authority notes that Rule 29(2) expressly empowers the Authority, upon establishing absorption, to recommend modification in the form or basis of the duty, or the quantum of the duty, or both, after reassessing the dumping and injury margins; and that Rule 31 permits a recommendation as to retrospective

application. The present investigation is confined to a re-determination of the dumping and injury margins in accordance with Rule 29(2); the extent, form and date of application of any modification are matters for the recommendation of the Authority in the final finding, to be made having regard to the lesser-duty rule. As regards user interest, issues of public interest were examined in the original investigation, and the domestic industry has demonstrated that the per-unit impact of the duty on the ultimate consumer is negligible. These contentions do not detract from the examination of absorption, which is undertaken below.

Absorption of anti-dumping duty

18. Rule 29(1) of the Anti-Dumping Rules provides that an anti-dumping duty may be considered to be absorbed when the export prices of an article from the exporting country decrease post imposition of the anti-dumping duty without any commensurate change in the cost of production of such article, or the export prices of such article to countries other than India, or the resale price of such article in India. The use of the word “or” makes it clear that the satisfaction of any one of the three conditions, together with a decline in the export price to India, is sufficient to establish absorption. The examination below is undertaken accordingly.

Transaction-wise imports of the subject goods during the absorption period

19. The transaction-wise data obtained from DG Systems for the absorption period records the following imports of the subject goods from the subject country.

Sl. No.	BE date	CTH	Quantity (kg)	Assessable value (₹)	CIF (₹/kg)	CIF (\$/kg)
1	***	38089390	15,000	***	***	15-16
2	***	38089399	5,000	***	***	5-6
3	***	38089399	23,000	***	***	15-16
4	***	38089399	23,000	***	***	15-16
	Total		66,000			

Source: DG Systems transaction-wise data. Values converted at Rs. 87.26 per US\$.

20. The Authority notes the following from the above data. **First**, the total volume of the subject goods imported during the absorption period is 66 MT. **Secondly**, the consignment at SN 1 was cleared on *** April 2025, prior to imposition of the anti-dumping duty on 8th May 2025; the post-imposition volume is 51 MT. **Thirdly**, and materially, the consignments at SN 1, 3 and 4 entered at CIF values in the region of the Minimum Import Price, whereas the consignment at SN 2, of 5 MT, entered at a CIF value that is, at, being approximately 38% of the level of the other consignments. The consignments at SN 1, 3 and 4 were imported by one of the responding importers from the participating exporter; the consignment at SN 2 was imported by an importer which has not participated, from an exporter in the subject country which has not participated.

21. **Fourthly**, the record establishes that the participating producer's own realisation on the subject goods was materially lower than the value at which those goods were exported to, and declared on import into, India. In response to verification, the participating parties furnished the producer's group transfer invoices, corroborated by contemporaneous entries in the producer's ERP system, evidencing the sale of the subject goods by the producer, M/s Xiangshui Zhongshan Bioscience Co., Ltd, to its related exporter, M/s Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd (a group company), on an ex-works realisation was in the range of approximately USD *** to *** per kg. The same consignments were invoiced by the related exporter for export to India, and declared before Indian customs, at approximately USD 15.0 to 15.2 per kg on a CIF basis. On the participating parties' own verified records, therefore, the value at which the producer parted with the subject goods was of the order of 35% to 45% of the value declared on importation into India.
22. The Authority is conscious that this ex-works transaction is one between related group companies and does not, of itself, constitute an arm's-length price capable of standing as the normal value or the export price, and it has not been so used. It is, however, the participating parties' own contemporaneous and verified record, and it is material for two reasons. It demonstrates that the value declared on import into India was maintained at or about the Minimum Import Price notwithstanding a substantially lower underlying realisation by the producer; and, it is closely consistent with the independent China Customs export data placed on record by applicants and with the below-MIP consignment at SN 2, thereby corroborating the conclusion that the effective price of the subject goods to India during the absorption period was materially below the declared import values and that the remedial effect of the duty in force has been undermined.

Reliance on actual export prices and the effect of the Minimum Import Price

23. The other interested parties have contended that the import prices reflected in the Indian customs data show no decline, and that the domestic industry enjoyed MIP protection throughout the absorption period. The Authority notes that the purpose of an anti-absorption investigation under Section 9A(1B) of the Act read with Rule 29 is to examine whether the exporters have reduced their actual export prices after imposition of the anti-dumping duty so as to absorb the effect of the duty. Such examination necessarily requires determination of the actual export prices charged by the exporters, and not the prices declared for compliance with other regulatory requirements. For the reasons recorded in paragraphs 19 to 21 above, the Authority has adopted the price of the consignment which entered free of the constraint of the Minimum Import Price, as corroborated by the China Customs export data, as representative of the actual export pricing of the subject goods to India. The mere existence of the MIP does not preclude a finding of absorption of the definitive anti-dumping duty.
24. The other interested parties have contended that any imports cleared below the MIP are a matter of customs/DGFT enforcement and not evidence of absorption within the jurisdiction of the Authority. The Authority notes that the MIP notified by the DGFT and the anti-dumping duty imposed under Section 9A of the Act are distinct instruments

operating under distinct statutory regimes. The examination of absorption of the anti-dumping duty falls squarely within the jurisdiction of the Authority under Section 9A(1B) read with Rule 29. The reliance on the actual export prices is for the limited purpose of examining the pricing behaviour of the exporters, and is not an exercise of enforcement of the MIP. The contention is not accepted.

25. The Authority has separately considered the commercial invoices and the corresponding customs export declarations of the subject country filed by the participating exporters, which record declared values on a CIF basis materially above the price adopted above. Those declared values correspond to the consignments at SN 1, 3 and 4 of the table at paragraph 19, which were cleared in the region of the MIP, and for the reasons recorded above such declared values reflect compliance with a distinct regulatory requirement rather than actual export pricing behaviour. The participating exporters have not placed on record their cost of production, or their transaction-wise third-country export prices, and have not claimed market economy treatment; they have therefore placed no verifiable material before the Authority which would displace the price adopted.

Movement in the cost of production

26. The other interested parties have contended that the raw-material costs of the domestic industry cannot be relied upon, and that Rule 29 requires examination of the cost of production in the exporting country. The Authority notes that, in the original investigation, the Chinese producers were held to be operating under non-market-economy conditions. In the present investigation, the participating exporters have neither claimed market economy treatment nor filed the market economy questionnaire. The Authority is therefore unable to rely upon the cost data of the exporters for examining whether the decline in export prices is commensurate with any decline in their cost of production. In the absence of verifiable cost information from the exporters, and consistent with the non-market-economy methodology adopted in the original investigation, the Authority has examined the movement in the globally prevailing prices of the major raw materials used in the production of the subject goods as a surrogate for the change in the cost of production. The relevant information is set out below.

Sl. No.	Particulars	UOM	Jan'23 to Dec'23	Jan'25 to Sep'25
1	Acetic Acid	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	84
2	Acrolein Technical	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	98
3	Ammonia Solution 24%	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	107
4	Caustic Soda Lye (32%)	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	102

Sl. No.	Particulars	UOM	Jan'23 to Dec'23	Jan'25 to Sep'25
5	Hydrogen Pipeline	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	101
6	Liquid Chlorine Pipeline	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	122
7	Magnesium Turnings	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	78
8	Methanol	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	112
9	Methyl Chloride	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	88
10	Phosphorus Trichloride	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	80
11	Sodium Cyanide	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	87
12	Triethyl Phosphite	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	91
	Total	₹/kg	***	***
	Trend	Indexed	100	93

27. It is seen that the aggregate of the prices of the relevant raw materials has declined by approximately Rs. 101 per kg (from Rs. ***/kg to Rs. ***/kg), i.e. by about 7.4%, during the absorption period.

Movement in the export price to India

28. In order to examine whether the export prices have declined following imposition of the anti-dumping duty, the Authority has compared the export price of the subject goods to India during the original period of investigation with the actual export price during the absorption period, determined as set out in paragraphs 19 to 22 above. The net export price has been derived from the CIF value by making the deductions set out below, so as to bring the price to an ex-factory level.

S. No	Particulars	UOM	₹/kg	\$/kg
1	CIF price	₹/kg	***	***
2	Less: Ocean freight (US\$ 80/MT)	₹/kg	***	***
3	Less: Marine insurance @ 0.05%	₹/kg	***	***

S. No	Particulars	UOM	₹/kg	\$/kg
4	FOB price	₹/kg	***	***
5	Less: Commission @ 3%	₹/kg	***	***
6	Less: Bank charges @ 0.5%	₹/kg	***	***
7	Less: Port expenses @ 0.5%	₹/kg	***	***
8	Less: Handling expenses @ 0.5%	₹/kg	***	***
9	Net export price	₹/kg	***	***

Exchange rate: Rs. 87.26 per US\$.

29. On the above basis, the net export price of the subject goods to India during the absorption period is USD *** per kg, as against the net export price of USD *** per kg determined in the original investigation. The export price has accordingly declined by approximately 46% following imposition of the anti-dumping duty. The ocean freight of *** per MT applied in the above computation has been determined from the shipping documents on record. The other interested parties have contended that the decline, if any, is on account of depreciation of the Indian rupee. The Authority notes that the export price is quoted in USD, and the decline is evident in USD terms; therefore, the decline cannot be attributed to exchange-rate movements. Since the export price is expressed and compared in the same currency, the exporters cannot contend that the decline is a consequence of rupee depreciation.

Export prices to third countries

30. The other interested parties have contended that the decline in the export price to India is commensurate with the decline in the export price to third countries, and that Rule 29 is therefore not satisfied. The Authority notes that, first, the participating exporters have not placed on record any transaction-wise export data to third countries to substantiate this claim, and the contention accordingly remains unsubstantiated. Secondly, and in any event, Rule 29(1) is disjunctive: a decline in the export price to India accompanied by the absence of a commensurate change in the cost of production is, by itself, sufficient to establish absorption, independent of the movement of third-country prices. As established above, the export price to India declined by about 46% while the price of the major raw materials declined by only about 7.4%. The decline in the export price is therefore not commensurate with the change in the cost of production, and the condition under the first limb of Rule 29(1) is satisfied. The contention is accordingly not accepted.
31. The Authority has examined the price at which the product under consideration was actually transacted in China PR during the absorption period. Three independent sources converge: the applicant's invoices of Chinese producers and traders, showing FOB prices in the range of USD 5.50–6.10/kg; the Chinese customs export data relied upon by the applicant, showing a weighted average FOB price in the range of USD 5.50–6.00/kg; and the participating exporter's own Appendix-1, reporting home-market realisation in the range of USD 5.50–6.00/kg. The exporter has itself stated that the article sold in China and

that exported to India are of the same quality and packing, and no difference in characteristics or terms of sale has been evidenced. The Authority accordingly holds it established that the product under consideration was sold in China PR during the absorption period in the range of USD 5.50–6.10/kg. This finding goes only to the price level; normal value continues on the basis adopted in the original investigation; the exporter having declined market economy treatment.

Resale price in India

32. The other interested parties have contended that the applicants have furnished no data relating to resale prices of the subject goods in India. The Authority notes that, the first limb of Rule 29(1) being satisfied for the reasons recorded above, and the provision being disjunctive, it is not necessary that the resale-price limb be independently satisfied. The Authority has nonetheless examined the material on record. Two importers, namely Zhongshan Crop Science India Pvt. Ltd. and Tephra Bioscience LLP, have filed questionnaire responses containing details of imports and of resale of the subject goods in India. On the data as filed, the resale prices of the imported subject goods in India during the absorption period stand above the corresponding landed values, and no declining trend in resale prices is discernible over the absorption period. The Authority further notes that the resale data on record relates to consignments cleared in the region of the MIP, and does not extend to the consignment at SN 2 of the table at paragraph 19, the importer of which has not participated in the present investigation.

Period of investigation and volume of imports

33. The other interested parties have contended that Rule 29 can be invoked only post-imposition of the duty, and that the inclusion of the pre-duty period within the 9-month absorption period is a jurisdictional error. The Authority notes that the analysis of absorption rests on the actual export pricing behaviour of the exporters after imposition of the anti-dumping duty on 8th May 2025. As appears from the table at paragraph 19, the consignment relied upon for the determination of the net export price was cleared on *** July 2025, that is, after the imposition of the duty; and the volume of post-imposition imports is 51 MT out of a total of 66 MT. The finding of decline in the export price is therefore not dependent upon the pre-duty transaction, and the inclusion of the earlier months within the descriptive period of absorption does not vitiate the analysis. The contention is, accordingly, not accepted.
34. The other interested parties have contended that the comparison of the absorption-period prices with the original POI has no legal basis, and that the 9-month period is arbitrary because Rule 5(3A) (ii) prescribes a normal 12-month POI. The Authority notes that Rule 29(1) itself contemplates a comparison of the export price “post imposition of the anti-dumping duty” with the basis on which the duty was originally determined; such comparison necessarily requires the export price of the original period of investigation as the benchmark, since the duty in force was determined on the conditions prevailing in that period. As regards the period of investigation, Rule 29 does not prescribe a fixed POI for an anti-absorption review; the period may be determined on the facts and circumstances of the

case, and the Authority recorded its reasons for adopting the 9-month period in the initiation notification. Rule 5(3A)(ii) governs the period of investigation for an original investigation and does not, of its own force, curtail the discretion available under Rule 29. The contention is not accepted.

35. The other interested parties have contended that the volume of imports at the lower price is too small to establish that the duty was rendered ineffective. The Authority records the position candidly: of the 51 MT imported after imposition of the duty, 5 MT, or approximately 10%, entered at the lower price, the balance having been cleared in the region of the Minimum Import Price. The Authority notes, however, that Rule 29 is directed at the pricing behaviour of the exporters and at whether such behaviour renders the anti-dumping duty ineffective, and not at any threshold volume of imports; neither Section 9A(1B) nor Rule 29 prescribes any minimum volume. The significance of the consignment at SN 2 lies not in its volume but in the fact that it is the only consignment during the absorption period which entered free of the constraint of the Minimum Import Price, and that it entered at a price at which the anti-dumping duty of USD 2,998/MT stands substantially neutralised, consistent with the China Customs export data covering a materially larger volume. The volume of imports at that price is, in the Authority's view, a function of the Minimum Import Price in force rather than of the pricing behaviour of the exporters, and is indicative of the likelihood of increased injurious imports upon any relaxation of the concurrent measure. The contention is not accepted.

Analysis on absorption

36. In light of the above, the Authority notes that while the price of raw material (by about 7.4%) and the surrogate cost of production have declined marginally whereas the export price of the subject goods to India has declined by about 46% following imposition of the anti-dumping duty. The decline in the export price is thus far greater than, and not commensurate with, the change in the cost of production. The table below summarises the degree of absorption by the exporters.

Sl. No.	Particulars	UOM	POI – OI	POI – AB
1	Net export price to India (Trend, indexed)	Indexed	***	***
2	Cost of raw material (Trend, indexed)	Indexed	100	93

37. The Authority, accordingly, notes that the export price of the subject goods from the subject country has declined post imposition of the anti-dumping duty without any commensurate change in the cost of production. The condition for absorption under Rule 29(1) is therefore satisfied. It is therefore concluded that the producers in the subject country have absorbed the measures. The Authority has proceeded to reassess the dumping margin and the injury margin in accordance with Rule 29(2), as set out in Section E.3 below.

Reassessment of dumping margin and injury margin

38. Rule 29(2) of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

“(2) Where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of the existing anti-dumping duty, and such duty is thereby rendered or maybe rendered ineffective, the designated authority may, after conducting review, recommend modification in the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum of anti-dumping duty, or both, after reassessing the dumping margin and injury margin and appropriate changes or adjustments in previously determined normal value and injury, if necessary, in accordance with the provisions of rule 10 and Annexure III to these Rules, respectively, may be done.”

39. The Authority notes that Rule 29(2) contemplates the making of “appropriate changes or adjustments in previously determined normal value and injury ... in accordance with the provisions of rule 10 and Annexure III to these Rules”. In exercise of that power the Authority has re-assessed the constructed normal value and the non-injurious price for the absorption period in accordance with Rule 10 and Annexure III respectively. The re-assessed NIP is approximately 14% lower than the NIP in original investigation, predominately due to reduction in raw material cost which is approximately 19%. Since the Chinese producers had not claimed market economy treatment at the time of the original investigation, and the participating exporters have not claimed such treatment in the present proceeding, the constructed normal value has been determined following the methodology adopted in the original investigation under para-7 of Annexure-I of the Rules. The Authority has not undertaken any fresh determination of injury to the domestic industry, the injury determination of the original investigation not being reopened in an anti-absorption review.

40. The re-assessed constructed normal value for the absorption period is as below.

Sl. No.	Particulars	Unit	POI – OI	POI – AB
1	Constructed normal value (CNV)	\$/kg	***	***
2	Exchange rate	₹/\$	83.52	87.26

41. The re-assessed non-injurious price for the absorption period is as below.

Sl. No.	Particulars	Unit	POI – OI	POI – AB
1	Non-injurious price	\$/kg	***	***
2	Exchange rate	₹/\$	83.52	87.26

42. Considering the re-assessed constructed normal value and the net export price of the subject goods determined at paragraph 27 above, the dumping margin for the subject goods from China PR has been determined as below.

Sl. No.	Particulars	CNV (\$/kg)	Net export price (\$/kg)	Dumping margin (\$/kg)	DM Range (%)
1	Original period	***	***	***	20–30%
2	Absorption period	***	***	***	85–95%

43. It is seen that the net export price to India has declined significantly from the original period to the absorption period, and that the decline in the net export price is steeper than the decline in the re-assessed constructed normal value. As a result, the dumping margin has risen from the range of 20–30% during the original period to the range of 85–95% during the absorption period, that is, approximately a three-fold increase. It is noted that the dumping margin of USD 2,998 per kg determined for the original period corresponds exactly to the anti-dumping duty of USD 2,998 per MT presently in force. The dumping margin now determined exceeds that amount by approximately USD *** per kg, which establishes that the anti-dumping duty in force has been absorbed by the exporters through a reduction in the export price and no longer offsets the dumping found.
44. It is therefore concluded that the dumping margin has increased.
45. Considering the re-assessed non-injurious price and the landed price of the subject goods, the injury margin for the subject goods from China PR has been determined as below.

Sl. No.	Particulars	NIP (\$/kg)	Landed price (\$/kg)	Injury margin (\$/kg)	IM Range (%)
1	Original period	***	***	***	20–30%
2	Absorption period	***	***	***	85–95%

46. It is seen that the landed price of the subject imports has declined from USD *** per kg during the original period to USD *** per kg during the absorption period, a reduction of approximately 45%, whereas the re-assessed non-injurious price has declined by approximately 18%. As a result, the injury margin has increased from the range of 20–30% during the original period to the range of 85–95% during the absorption period. The landed price of the subject imports continues to remain significantly below the non-injurious price even after accounting for the anti-dumping duty in force, confirming that the remedial effect of the duty has been undermined.

47. The landed value of imports has been determined on the basis of the assessable value together with the applicable duties of customs, in accordance with the consistent practice of the Authority.
48. It is therefore concluded that the injury margin has increased.

E. POST DISCLOSURE COMMENTS

E.1 Submissions made by other interested parties

49. The following comments have been filed by the interested parties.
- i. Decline in export prices was attributed to a global decline in Glufosinate prices, and not to absorption of the anti-dumping duty.
 - ii. Absorption must be determined exporter-wise, and country-wide data or transactions of a non-participating exporter cannot be used to establish absorption against individual exporters.
 - iii. Only 5 MT out of 51 MT of post-duty imports were at the lower price; such limited and isolated imports cannot establish that the duty was rendered ineffective.
 - iv. The 5 MT transaction was specifically challenged as non-representative, particularly as it involved a non-participating exporter and was outside the MIP framework.
 - v. Only about four months of post-duty data were available, which was claimed to be insufficient for determining absorption.
 - vi. The operation of MIP was relied upon to contend that the MIP-compliant transactions, rather than isolated below-MIP imports, should be considered for assessing actual pricing behaviour.
 - vii. The approach was alleged to be inconsistent with DGTR's past practice of requiring exporter-specific evidence.
 - viii. Clarification was sought regarding applicability of Rule 2(b), Rule 5(3A) (ii) and the requirement of exporter-specific evidence for an absorption finding.
 - ix. Selective reliance on the Original Findings was challenged, particularly the alleged disregard of the global decline in prices.
 - x. The Rule 2(b) eligibility of UPL as DI was questioned on the basis of possible relationship/imports, and verification was requested.
 - xi. The proposed modification/retrospective application of duty was also challenged.

E.2 Submissions made by domestic industry

50. The following comments have been filed by the domestic industry.
- i. The 46% decline in export price, against only 7.4% decline in major raw-material prices, demonstrates that the reduction in export price was not commensurate with the decline in cost of production and therefore establishes absorption under Rule 29(1).

- ii. The decline in export price is evident in both USD and INR terms; hence, the contention that the decline was due to rupee depreciation is not sustainable.
- iii. Rule 29(1) provides three alternative parameters for absorption; satisfaction of any one condition is sufficient and all three conditions need not be established simultaneously.
- iv. The existence of a global decline in prices does not by itself negate absorption, since the relevant test is whether the reduction in export price to India was commensurate with the change in cost of production; in the present case, the export-price decline substantially exceeded the raw-material cost decline.
- v. Limited import volume does not preclude absorption; the relevant consideration is the pricing behaviour and whether it undermines the remedial effect of the duty. The 5 MT imports below MIP therefore remain relevant.
- vi. The 5 MT transaction cannot be disregarded merely because of its limited quantity; the exporter failed to provide evidence establishing that the MIP-compliant prices represented its independent pricing behaviour.
- vii. MIP and ADD are distinct measures. MIP compliance does not prevent examination of actual export prices, and MIP cannot substitute for an effective anti-dumping duty.
- viii. The January–September 2025 absorption period is appropriate, as Rule 29 does not prescribe a minimum post-duty period; further, the transactions forming the basis of the finding occurred after imposition of ADD on 8 May 2025.
- ix. The reliance on Kalyani Steels and Rule 5(3A) (ii) was stated to be misplaced since the present review is governed by Rules 29 and 30 and Rule 29 does not prescribe the 12-month POI requirement applicable to original investigations.
- x. China Customs data should be considered for export-price determination as it represents the price at which the goods were exported, whereas Indian CIF values may reflect MIP-compliant declared values rather than actual export prices.
- xi. Where complete exporter-specific information is not provided, the Authority may rely on best information available under Rule 6(8).
- xii. The dumping and injury margins increased to 85–95%, while landed price declined by about 45% against only 18% decline in NIP, demonstrating that the duty remained ineffective.
- xiii. The Rule 2(b) objection regarding DI standing requires verification of the alleged relationships/imports; however, the available submission specifically requests such verification and does not itself establish disqualification.
- xiv. On the form of duty, ad-valorem duty was sought considering variations in product form, concentration and transaction value.
- xv. The impact of ADD on downstream users was submitted to be minimal, estimated at approximately ₹35–36 per bottle

E.3 Examination by the Authority

51. The Authority notes that, following imposition of the anti-dumping duty, the export price of the subject goods to India declined by approximately 46%, whereas the prices of the major raw materials declined by only about 7.4% over the same period. A fall in the export price of that magnitude is not explained by the movement in input costs, and the decline is evident whether measured in US Dollars or in Indian Rupees. It cannot, therefore, be attributed merely to exchange-rate fluctuation or to movements in global prices; it reflects a reduction in the export price that is not commensurate with any corresponding change in the cost of production.
52. The Authority is equally unable to accept that the volume of below-MIP imports is too small to sustain a finding of absorption. An examination under Rule 29 is directed to the exporters' pricing behaviour and to the continued effectiveness of the duty, and neither Rule 29 nor Section 9A(1B) of the Act prescribes any minimum volume of imports as a condition for such a finding. What is material is whether the export price to India has declined, after imposition of the duty, in a manner that undermines its remedial effect; the quantity of imports at which that decline is evidenced does not determine the question. Moreover, the pricing behaviour in question is not confined to the below-MIP consignment. The consignments of the participating exporter were declared on import at values at or about the Minimum Import Price only by reason of compliance with that price; their actual net export price, as established by the exporter's own verified records — its group transfer invoices corroborated by its ERP delivery notes — was in the range of USD 5.85 to 6.25 per kg, that is, at substantially the same level as the consignment that entered free of the MIP constraint. The participating exporter's own consignments thus exhibit the same reduction in the actual export price, and the fact that the below-MIP consignment represented only of the order of 10% of the total volume imported after imposition of the duty does not, by itself, preclude a finding of absorption.
53. The 5 MT imports at USD 5.5–6/kg are relevant as they reflect prices below MIP. The remaining imports cleared around MIP cannot, without supporting evidence, be treated as representative of independent commercial pricing, particularly where the exporter has not substantiated the same.
54. MIP and anti-dumping duty are separate, distinct measures under different legislations. MIP-compliant declared prices may reflect regulatory compliance and do not necessarily represent actual export prices. Accordingly, actual export prices, including relevant China Customs data and supporting invoices, have been considered. The Authority further notes that the declared import values were held at or about the Minimum Import Price (MIP) only by operation of that price, whereas the actual export prices were materially lower. Had that MIP not been in operation, the subject goods would in all likelihood have entered at these substantially lower prices, resulting in a surge of imports at landed values well below the non-injurious price. The MIP has thus, for the present, masked the reduction in the actual export prices at the border; it has not cured the absorption of the anti-dumping duty. This reinforces the conclusion that the remedial effect of the duty in force has been undermined.

55. Where complete transaction-wise/third-country information has not been furnished despite opportunity, the Authority is entitled to rely on best information available under Rule 6(8).
56. The Authority notes that Rule 29 does not prescribe a minimum post-duty period. The relevant transactions forming the basis of the absorption finding occurred after 8 May 2025; therefore, the inclusion of the earlier period does not invalidate the examination.
57. Rule 5(3A) (ii) relates to the POI requirement applicable to original investigations under Rule 5 and cannot be mechanically applied to the present review conducted under Rules 29 and 30.
58. The Authority has considered the submission regarding exporter-wise examination and past DGTR practice. The determination is based on the evidence available in the present investigation, including the pricing information on record; absence of complete exporter-specific information, where applicable, is dealt with under Rule 6(8).
59. The Authority has also considered the Rule 2(b) objection regarding DI standing/possible related-party imports. The applicants have a related importer in UAE, which is a non-subject country and there is no evidence in place to show that the product purchased by the entity in UAE has been then exported to India. Therefore, the Authority considers that there is no outstanding issue with regard to eligibility of the applicant with regard to Rule 2(b).
60. On reassessment, the dumping and injury margins increased to 85–95%, while landed price declined by about 45% against an approximately 18% decline in NIP, establishing that the landed price remained significantly below NIP even after the duty.
61. Accordingly, the Authority finds that the decline in export price was not commensurate with the decline in cost of production and that the existing anti-dumping duty has been rendered ineffective within the meaning of Rule 29. The appropriate modification in the quantum of duty has consequently been examined under Rule 29(2)

F. CONCLUSION

62. After examining the submissions made by all the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes as below,
 - a. The application for initiation of the present anti-absorption investigation was filed by the applicants as producers of the like article in India, in accordance with Rule 30 of the Rules, and the investigation was initiated vide notification No. 7/02/2026-DGTR dated 2nd March 2026.
 - b. The scope of the product under consideration is the same as that in the original investigation, that is, Glufosinate and its salts, both in technical and formulation form; the subject goods produced by the domestic industry are the like article; and the determinations of the original investigation as to standing, injury and causal link are not reopened.

- c. The DG Systems transaction-wise data records imports of 66 MT of the subject goods during the absorption period, of which 51 MT were imported after imposition of the anti-dumping duty on 8th May 2025. Of the post-imposition volume, 5 MT entered under a tariff item outside the coverage of the Minimum Import Price, at a CIF value of USD *** per kg, and the balance entered in the region of the Minimum Import Price.
- d. The price of the consignment which entered free of the constraint of the Minimum Import Price is closely consistent with the FOB export prices appearing in the China Customs export data placed on record by the applicants, and has been adopted as representative of the actual export pricing of the subject goods to India.
- e. On that basis the net export price during the absorption period is USD *** per kg, as against USD *** per kg determined in the original investigation, a decline of approximately 46%.
- f. The participating exporters have neither claimed market economy treatment nor filed the market economy questionnaire, and their cost data is accordingly not available in a verifiable form; the change in the cost of production has been examined on the basis of the movement in the prices of the major raw materials as a surrogate, which shows a decline of about 7.4%.
- g. The decline in the export price to India is therefore not commensurate with the change in the cost of production, and the condition for absorption under the first limb of Rule 29(1) is satisfied.
- h. The participating exporters have placed no transaction-wise third-country export data on record, and the resale-price data on record does not independently indicate absorption; Rule 29(1) being disjunctive, the finding rests on the first limb.
- i. On re-assessment under Rule 29(2), and the constructed normal value is USD *** per kg and the non-injurious price USD *** per kg for the absorption period.
- j. The dumping margin has increased from the range of 20–30% in the original period to the range of 85–95% in the absorption period, and the injury margin from the range of 20–30% to the range of 85–95%. The dumping margin determined for the original period, being USD 2.998 per kg, corresponds to the anti-dumping duty presently in force. In per-unit terms the re-determined dumping margin, being ***, is the lesser of the two margins.
- k. The landed price of the subject imports continues to remain significantly below the non-injurious price even after accounting for the anti-dumping duty in force.
- l. Accordingly, the anti-dumping duty in force has been absorbed by the exporters and rendered ineffective within the meaning of Section 9A(1B) of the Act read with Rule 29 of the Anti-Dumping Rules.

- m. The modified quantum of anti-dumping duty shall apply prospectively only, without retrospective effect, while the existing form of duty shall remain unchanged and only its quantum shall be modified.

G. RECOMMENDATION

63. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of absorption. Having initiated and conducted the investigation into absorption of duty on Chinese producers in terms of the provisions laid down under the Anti-dumping Rules, the Authority is of the view that modification of anti-dumping duty applicable on Chinese producers are required. Therefore, the Authority recommends modification of quantum of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.
64. The Authority recommends modification of quantum of anti-dumping duty imposed on imports of subject goods originating in or exported from China PR vide Final Finding Notification No. F. No. 6/19/2024-DGTR dated 10th February 2025 and Notification No. 09/2025-Customs (ADD) dated 8th May 2025 as below. Taking into account factual matrix of the case, and having regard to information provided, and submissions made by interested parties, it is considered appropriate to modify the quantum of definitive anti-dumping duty. The modified quantum of anti-dumping duty shall have prospective application only and shall not operate retrospectively, while the existing form/type of anti-dumping duty shall remain unchanged, with only the quantum being modified.
65. The Authority has considered the domestic industry's request under Rule 31 for retrospective application of the modified duty from the date of initiation, and the recommendation of provisional assessment under Rule 30(5) made at initiation. Rule 31 enables, but does not compel, retrospective application, the matter being one for the Authority's discretion having regard to the remedial object of the review and the lesser-duty principle. That object is remedial, not penal, and is achieved in full by prospective modification of the duty. The subject goods entered India, during the review, at declared values at or about the Minimum Import Price that is, at or above the non-injurious price and bore the duty then in force, and no decline in their resale price in India has been established; there was thus no influx at injurious landed values for a retrospective duty to counter. This is distinct from the finding of absorption, which rests on the exporters' actual export-pricing behaviour and warrants re-determination of the duty prospectively. Applying the lesser-duty principle, the Authority considers prospective application adequate and does not recommend retrospective application; imports subjected to provisional assessment under Rule 30(5) are accordingly to be finally assessed at the rate of duty in force during the relevant period.
66. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of antidumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends modification of the quantum of anti-dumping duty on imports of the subject goods

originating in or exported from the subject country to the amount specified in Column 7 of the duty table appended below. The modified duty shall take effect prospectively from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, and shall remain in force for the unexpired period of the anti-dumping duty imposed vide Notification No. 09/2025-Customs (ADD) dated 8th May 2025.

DUTY TABLE

S. No.	Heading /Subheading*	Description of the goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 and 38089999	Glufosinate and its salt	China PR	Any other country including China PR	Any	5004	MT	USD
2	-do-	-do-	Any Country other than China PR	China PR	Any	5004	MT	USD

*The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration

H. FURTHER PROCEDURE

67. An appeal against the order of the Authority arising out of the final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

AMITABH KUMAR, Designated Authority